प्रकाशन का 43 वां वर्ष

शैल समाचार

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक-24 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 11-18 जून 2018 मूल्य पांच रूपए

क्या अभी तक नहीं बन पा रही जयराम की स्वीकार्यता

शिमला/शैल। क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कुर्सी के लिये अभी भी खतरे के बादल बरकरार है यह सवाल मुख्यमन्त्री के अपने ही ब्यान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बन गया है। जयराम ने प्रैस क्लब शिमला के एक आयोजन में जब यह कहा कि पहले कोई और मुख्यमन्त्री बन रहा था लेकिन अब जयराम बन गया है। ''बन गया है तो स्वीकार भी कर लो'' तब इस ब्यान पर हर कोई हैरान था। क्योंकि प्रदेश की जनता ने तो भाजपा को पूरा बहुमत देकर सत्ता में बैठा दिया है और इसे विपक्ष से कोई खतरा नही है। यदि जयराम को कोई खतरा होगा तो वह अपनी ही पार्टी से होगा। यह स्वभाविक है कि जब जयराम मुख्यमन्त्री बन गये हैं तो पार्टी के भीतर तो उनके ही समकक्ष या वरिष्ठ है उनके मन मे भी इस कुर्सी पर बैठने की ईच्छा होना कोई अपराध नही है। हाईकमान को सरकार से परिणाम चाहिये। उसमें अब पहला टैस्ट आ रहा है लोकसभा चुनावों का इसमें हाईकमान को यदि जयराम फिर से प्रदेश की चारो सीटें जीतकर दे देते हैं तो उनकी कुर्सी को कोई खतरा नही होगा। यदि ऐसा नही हो पाता है तो फिर हाईकमान को सोचने का मौका मिल जायेगा। पार्टी के भीतर बैठे दूसरे लोगों को भी यह कहने का मौका मिल जायेगा कि इस नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव सुरक्षित नही होगा। राष्ट्रीय दलों में आकलन का मानदण्ड यही रहता है।

इस आईने में यदि जयराम के पांच माह के कामकाज का आकलन किया जाये तो स्थिति कोई बहुत सुखद नज़र नही आती है। अभी जो पेयजल का संकट राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य जिलों मे पेश आया है उसमें सरकार के प्रयास और प्रबन्धन कितने पाकसाफ रहे हैं इसका अन्दाजा उच्च न्यायालय की टिप्पणी से ही लग जाता है। उच्च न्यायालय ने इस संकट के लिये जिम्मेदार लोगों को चिहिन्त करके उनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये थे और अदालत को इससे अवगत करवाने के भी निर्देश दिये थे लेकिन जब मुख्य सचिव और आयुक्त नगर निगम ने इस पर उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर किया तो उस पर अदालत की यह टिप्पणी आयी है We notice the affidavit of the chief Secretary, Govermenet of Himachal Pradesh and the Commissioner, Municipal Corporation, shimla to be conspicuously silent of the action taken against such of those persons whose acts of omission and commission led to the situation of crisis. we are assured that appropriate action in this regard shall positively be taken before the next date of hearing.

इसी तरह आईजीएमसी शिमला में पार्किंग की समस्या को लेकर आयी एक जनहित याचिका की सुनवाई में भी उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी आयी है Despite repeated opportunities, no reply has been filed on behalf of respondents No.1 to 3 and 5. Respondent No.4, Municipal Corporation, Shimla has filed its reply. This Court in many other petitions repeatedly cautioned respondent-State with regard to manifold increase in traffic in Shimla town, where admittedly roads are congested and there is very little scope of expansion. Recently, this Court in CWPIL No. 19 of 2016 titled Court on its own motion versus State of Himachal Pradesh and others, taking note of affidavit having been filed by Deputy Commissioner, Shimla had directed the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh to set up a Committee to look into parking and traffic problem in Shimla town, but it appears that none in the helm of affairs is actually bothered about problem of traffic/parking

शिक्षा विभाग में अध्यापकों की कमी को लेकर आयी एक याचिका में उच्च न्यायालय ने विभाग के शपथ पत्र पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सचिव शिक्षा को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर रहने के आदेश किये हैं। ऐसे ही कई और मामलों में उच्च न्यायालय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा चुका है।

उच्च न्यायालय की शीर्ष प्रशासन को लेकर आयी ऐसी टिप्पणीयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शासन और प्रशासन में सब कुछ सही नही चल रहा है। जब प्रदेश का उच्च न्यायालय शीर्ष प्रशासन को लेकर इस तहर की टिप्पणी करेगा तो इससे प्रदेश की जनता में सरकार को लेकर क्या संदेश जायेगा। उच्च न्यायालय की इन टिप्पणीयों से हटकर भी यदि सरकार का आकलन किया जाये तो यह सामने आता है कि अब तक प्रशासन पर मुख्यमन्त्री की पकड़ नही बन पायी है। क्योंकि एक ओर तो सरकार राजस्व को पहुंचे नुकसान के कारणों की जांच करवाने की बात कर रही है और दूसरी ओर कर्ज लेकर घी पीने की कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है। पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन को उनकी सेवानिवृति के एक वर्ष बाद जिस तर्क पर स्टडी लीव दी गयी है वह अपने में ही एक घोटाला बन गया है। राज्य के राजस्व को कहां और कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है यह एक जनचर्चा बन चुका है। विभिन्न निगमों/बोर्डो में कार्यकर्ताओं की ताजपोशीयां रूकी हुई हैं जबकि कई जगह ऐसा कर दिया गया है कि जिन्हे कांगेस ने ताजपोशी दी थी उन्हे इस सरकार ने भी ताजपोशी दे दी है। कार्यकर्ताओं में एक अधिकारी की पत्नी को समाज कल्याण बोर्ड में दी गयी तैनाती पर रोष देखने को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस के वीरभद्र शासन में भी इन्हे यह ताजपोशी मिली हुई थी। उच्च न्यायालय सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर आये दिन कोई न कोई टिप्पणी कर रहा है। जिससे यह संदेश जा रहा है कि शायद सरकार के महाधिवक्ता और उनकी टीम उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रभावी ढ़ग से नहीं रख पा रहे हैं। रिटायर्ड लोगों को फिर से नौकरी में वापिस बुलाया जा रहा है जबकि वीरभद्र सरकार को इसके लिये हररोज कोसा जाता था। जब सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर इस तरह की चर्चाएं लगातार बाहर आती जायेंगी तो निश्चित रूप से प्रशासन और जनता में शीर्ष नेतृत्व की स्वीकार्यता को लेकर सवाल उठेंगे ही। शायद यही अन्दर की ऊहा-पोह मुख्यमन्त्री के इस ब्यान में अनायास ही बाहर आ गयी है।

पांच माह में ओक ओवर से सचिवालय नही पहुंचा मांग पत्र

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर को पूर्व कर्मचारी नेता ओम प्रकाश गोयल ने उनके सरकारी आवास ओक ओवर में 18 फरवरी को एक करीब 190 पेज का प्रतिवेदन सौंपा था। इस प्रतिवेदन में गोयल ने उस सबका देस्तावेजी प्रमाणों के साथ खुलासा किया था जो उनके साथ पर्यटन विकास निगम में पेश आया था जब उन्होने निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का ईनाम उन्हे नौकरी से बर्खास्तगी के रूप में मिला जबकि हर सरकार भ्रष्टाचार कतई सहन नही किया के दावे करती आयी है। यही नही भाजपा ने जब 6.3.2007 को महामहिम राज्यपाल को तत्कालीन वीरभद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र सौंपा था तब जयराम ठाकुर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस आरोप पत्र में वीरभद्र सरकार पर एक आरोप कर्मचारियों के उत्पीडन का था और इस उत्पीड़न में वाकायदा ओम प्रकाश गोयल का नाम शामिल था। आरोप पत्र प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के हस्ताक्षरों से सौंपा गया था। लेकिन जब धूमल सरकार सत्ता में आयी तो तब गोयल को इन्साफ नही मिल पाया। इसके बाद वीरभद्र सरकार सत्ता में आयी। इस सरकार ने गोयल के आरोपों की जांच के लिये पर्यटन निगम के एक निदेशक धर्माणी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। धर्माणी कमेटी ने गोयल के लगाये आरोपों को एकदम सही पाया और न्याय दिये जाने की संस्तुति की। लेकिन इतना होने के बावजूद वीरभद्र काल में गोयल को न्याय नही मिल पाया।

अब जब जयराम की सरकार आयी तब 18 फरवरी को गोयल ने मुख्यमन्त्री आवास ओक ओवर में फिर मुख्यमंत्री को न्याय की गुहार लगाते हुए एक प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमन्त्री जयराम ने उन्हे पूरा आश्वासन दिया कि उनको इन्साफ मिलेगा। गोयल ने मुख्यमन्त्री के साथ ही इस प्रतिवेदन की प्रतियां महामहिम राज्यपाल, शिमला के विधायक एवम् शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज और प्रदेश के मुख्य सचिव को भी सौंपी। इसके बाद जब 8.3.2018 को आरटीआई के तहत गोयल ने अपने इस प्रतिवेदन पर अब तक हुई कारवाई के बारे में जानकारी मांगी तब विशेष सचिव पर्यटन के कार्यालय से उन्हे जवाब मिला कि उनके प्रतिवेदन को लेकर राज्यपाल, शिक्षा मन्त्री और मुख्य सचिव के कार्यालयों से तो पत्र प्राप्त हुए हैं लेकिन मुख्यमन्त्री कार्यालय से कोई पत्र नही मिला है। इस पर गोयल ने मुख्यमन्त्री कार्यालय से भी जानकारी मांगी और वहां से भी जवाब आया कि मुख्यमन्त्री कार्यालय में उनका कोई पत्र प्राप्त ही नही हुआ है।

आरटीआई में मिली इस सूचना के बाद फिर गोयल ने मुख्यमन्त्री के आवास पर दस्तक दी। इस बार बड़ी प्रतीक्षा के बाद मुख्यमन्त्री को मिल पाये। लेकिन मिलने पर इसका कोई जवाब नही मिल पाया कि उनके प्रतिवेदन का हुआ क्या है। इस बार भी उन्हे केवल आश्वासन ही मिला है कि वह उनकी फाइल मंगवायेंगे। इस सबसे यह सवाल उठता है कि जब मुख्यमन्त्री के आवास पर दिया गया प्रतिवेदन ही पांच माह में आवास से कार्यालय तक न पहुंच पाये और न ही संवद्ध विभाग में

Om Parkash Goel,
M.Com, LLB and DPM & IR,
Ex Senior Accountant, HPTDC,
Advocate,
No.

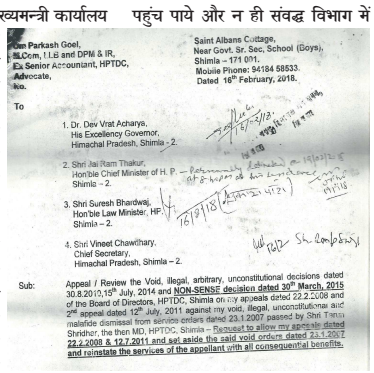

Saint Albans Cottage,
Near Govt. Sr. Sec, School (Boys),
Shimla – 171 001.
Mobile Phone: 94184 58533.
Dated 16th February, 2018.

To

1. Dr. Dev Vrat Acharya,
His Excellency Governor,
Himachal Pradesh, Shimla – 2.
2. Shri Jai Ram Thakur,
Hon'ble Chief Minister of H. P. – Personally delivered @ 19/02/2018 at 8.40 pm at his residence
Shimla – 2.
3. Shri Suresh Bhardwaj,
Hon'ble Law Minister, HP.
Shimla – 2.
4. Shri Vineet Chawdhary,
Chief Secretary,
Himachal Pradesh, Shimla – 2.

Sub: Appeal / Review the Void, illegal, arbitrary, unconstitutional decisions dated 30.8.2010,15th July, 2014 and NON-SENSE decision dated 30th March, 2015 of the Board of Directors, HPTDC, Shimla on my appeals dated 22.2.2008 and 2nd appeal dated 12th July, 2011 against my void, illegal, unconstitutional and malafide dismissal from service orders dated 23.1.2007 passed by Shri Tarun Shridhar, the then MD, HPTDC, Shimla – Request to allow my appeals dated 22.2.2008 & 12.7.2011 and set aside the said void orders dated 23.1.2007 and reinstate the services of the appellant with all consequential benefits.

शेष पृष्ठ 7 पर..............................

भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रोबेशनर्ज ने की राज्यपाल से मुलाकात

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत से हिमाचल प्रदेश कॉडर के पांच आईएएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने मुलाकात की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये प्रोबेशनर्ज हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलॉन शिमला में राज्य विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

बातचीत के दौरान राज्यपाल ने उम्मीद जताई की नौजवान लड़कों और लड़कियों का प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में आने से शासन व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि अपने कार्य के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना आवश्यक है, क्योंकि इससे न केवल उनका अपना भविष्य, बल्कि देश का भविष्य भी प्रभावित होगा।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि 'आप सभी नौजवान हैं और खुश किस्मत हैं, क्योंकि देश की सेवा करने का अवसर मिला है। अपनी प्रतिभा से दूसरों के लिए प्रेरणा स्तोत्र बनें तथा समाज व राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। युवा अधिकारियों के माध्यम से कार्य संस्कृति प्रभावी होगी। अपनी सेवा के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाएं।'

राज्यपाल ने आईएएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों को पर्यटन, जल संग्रहण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी।

आचार्य देवव्रत ने उनके सफल एवं यादगार कार्यकाल की शुभकामनाएं दी।

छात्राओं के लिए स्थापित होगें पाँच मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य में लड़कियों के कल्याण व उत्थान के लिए शीघ्र बोर्ड गठित करेगी ताकि प्रदेश की बेटियों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में श्रेष्ठ बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 10 मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय खोले जाएगे जिनमें से पांच विद्यालय केवल लड़कियों के लिए होंगे। मुख्यमंत्री मानवी संस्था द्वारा आयोजित 'बेटियों को सम्मान' समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी समाज में बेटे के जन्म को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन बेटियों के जन्म पर उत्साहीनता देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ सामाजिक बुराईयों व पुराने मिथ्यों के कारण है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार के प्रयासों तथा लोक जागरूकता के कारण लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह समय की आवश्यकता है कि हम सभी सुदृढ़ व प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महिलाओं के कल्याण व उत्थान के लिए मिलजुल कर कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि महिला सशक्तिकरण व बालिका को समान अधिकार के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा व उत्थान के लिए गुड़िया हैल्पलाइन तथा शक्ति एप्प आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सही अर्थों में महिला उत्थान व स्वच्छता अभियान पर ध्यान केन्द्रित किया है। यह दोनों ही मामले उनके प्रिय हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 24 लड़कियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार जीतने वाली बेटियों के उज्ज्वल व खुशहाल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से पुरस्कार प्राप्त करने वाली 24 लड़कियों को 21 हजार रुपये देने की भी घोषणा की।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में पूर्व में भी रही भाजपा की सरकारों ने महिलाओं के कल्याण व उत्थान के लिए हमेशा ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि आज केन्द्र में रक्षा एवं विदेश मंत्रालय की मुखिया महिला है, जो नरेन्द्र मोदी सरकार की देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति व सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया है, परन्तु दुर्भाग्य से अनेक सामाजिक बुराईयों के कारण इसमें कमी आई है। उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए मिल-जुल का कार्य करना चाहिए ताकि महिलाओं को विकास व प्रगति के समान अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण व उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, परन्तु लिंगानुपात में गिरावट चिन्ता का विषय है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं को आरम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजेन्द्र फड़के ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वरोज़गार व अन्य क्षेत्रों के लिए 147 कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने सामाजिक संगठनों व गैर सरकारी संगठनों से कन्या भ्रूण हत्या व लिंग परीक्षण जांच जैसी सामाजिक बुराईयों पर नजर रखने के लिए आगे आने का आग्रह किया।

राज्यसभा की पूर्व सांसद विमला कश्यप ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर संस्थान की विभिन्न गतिविधियों बारे जानकारी दी।

निःशुल्क हवाई एम्बुलेंस सेवाओं के लिए समझौत ज्ञापन पर हस्ताक्षर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी स्वास्थ्य उप-केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं वैलनेस केन्द्रों में परिवर्तित कर स्वास्थ्य कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत' को कार्यान्वित करेगी। इसके अन्तर्गत निर्धन लोगों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा छत्र प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री निःशुल्क हवाई एम्बुलेंस सेवा को आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार, हैलीमिशन फाउंडेशन स्विट्जरलैंड तथा लेडी विलिंटन अस्पताल मनाली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने स्विट्जरलैंड हैलीमिशन फांउडेशन का प्रदेश में लेडी विलिंटन अस्पताल मनाली के साथ निःशुल्क हवाई एम्बुलेंस सेवा आरम्भ करने के प्रस्ताव के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस हवाई एम्बुलेंस सेवा से पूरे प्रदेश के मरीजों को नजदीक के स्वास्थ्य संस्थान के लिए लिफ्ट किया जा सकेगा और यह 108 एम्बुलेंस सेवा के निकट समन्वय के साथ क्रियाशील होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध करवाएगी जिनमें मानव संसाधनों के लिये आवासीय स्थान, लैण्डिंग व हैलिकॉप्टर का रख-रखाव इत्यादि शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घरद्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2302 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, जो गत वर्ष के बजट से 582 करोड़ रुपये अधिक है।

हैलीमिशन फांउडेशन स्विट्जरलैंड के अन्तर्राष्ट्रीय निदेशक सीमन टैनर ने कहा कि फांउडेशन इस क्षेत्र में गत 47 वर्षों से कार्य कर रही है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-PROCUREMENT NOTICE NOT SENT FOR PUBLISHED
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HPPWD Barsar Division H.P on behalf of Governor of H.P invited/re-invited the item rate bids, in electronic tendering system, for each of the following works from the eligible and approved contractors registered with HPPWD:-

Name of work :-1.:- C/o 1 No.Type-1 Qtrs. At Degree Collage Bhoranj(SH:- building portion including WS and S.I) Estimated Cost Rs. 9,48,204/- Earnest Money Rs. 19,000/- Time limit six month cost of Form Rs. 350/-

2. Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: **10.07.2018 from 10.30 A.M.**
3. Cost of Bid Form:-Rs. 350/- (non-refundable) only in form of demand draft in favour of Executive Engineer HPPWD Barsar.
4. Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submitted online on website http://hptenders.gov.in bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: **http://hptenders.gov.in** Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.
5. Submission of Original Documents: The bidder are required to submit (i) Original demand draft towards the cost of bid document and (ii) Original earnest money in the approved from duly pledged in the name of Executive Engineer, Barsar Division, HP.PWD., Barsar.(iii) All required Affidavit in original duly attested by Executive Magistrate/Notary. The above documents shall be submitted by the contractor on the date of opening of the bid failing which tender will not be opened.
6. Last Date/Time for receipt of bids through e-tendering :- **18.07.2018upto 10.30 A.M**
7. The site for the work is available.
8. Only online submission of bids is permitted, therefore; bids must be submitted online on website **http://hptenders.gov.in.**The bids shall be opened on **18.07.2018 at 11.30 A.M.** in the office **Executive Engineer Barsar Division H.P.P.W.D., Barsar (H.P.)** by the authorised officer. In the interest of tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
9. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than One hundred twenty days after the deadline date for bid submission.
10. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-1071/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
'NOTICE INVITING TENDERS'

Sealed item rate tenders on form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Palampur Division HP.PWD., Palampur on behalf of the Governor of H.P for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP.PWD, (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before on **16.07.2018 up to 11.00 AM.** And the same shall be opened on the same day at **11.30 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (Non-refundable) on **13.07.2018 up to 4.00 P.M** and the application for issue of tender form shall be received on **12.07.2018 up to 12.00 noon.**

The earnest money in the shape of NSC/FDR/saving account of the Post office/Bank in H.P duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional/ incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost (In Rs.)	Earnest Money	Time limit	Cost of Tender form
1.	C/O Link road from Durga Mandir Pathiar to Harizan Basti (SW:-C .C Pavement work at RD 2/350 to 2/373).	4,71,948/-	9500/-	Two Months	350/-
2.	C/O Link road from Durga Mandir Pathiar to Harizan Basti (SW:- C/O R/Wall at RD. 2/350 to 2/375).	4,92,425/-	9900/-	Two Months	350/-
3.	C/O Parour Lahla Chachian road (SW:-C/O R/Wall at km 5/ 200 to 5/230)	2,65,188/-	5400/-	Two Months	350/-
4.	C/O Rit to Jamrara via Jamrara Badhala Khota Kasba Kotlu Barla road Km. 0/00 to 8/00. (SW:- C/O 2.00 Mtr. span culvert at Rd. 0/005).	3,92,906/-	7900/-	Four Months	350/-
5.	C/O Lahat Kuthera Ladhi road Km. 0/00 to 5/000. (SW:- P/L C. C Pavement at Rd. 0/600 to 0/675).	252118/-	5100/-	Two Months	350/-

Terms & Conditions:-
Following documents should accompany the application for tenders.
1. Sale tax No. with latest Sales tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic/Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered/ Insured post which should be received in this office on or before the date of opening of tender by 11.00 A.M positively.
7. Contractor should have successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost during the last preceding three years
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand . Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-1107/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

हिमाचल प्रदेश के लिए 1900 करोड़ की पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजना स्वीकृत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित लगभग 1900 करोड़ रुपये की पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इससे हिमाचल प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नई परियोजना से हम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के अनछुए पर्यटन गंतव्यों को विकसित करने और शहरों में अधोसंरचना स्तरोन्नत करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रदर्शित कर सकेंगे।

इससे पूर्व, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिंह ने आर्थिक मामले विभाग में इस परियोजना पर प्रस्तुति दी और बताया कि यह परियोजना आठ वर्षों की अवधि में पूरी होगी। परियोजना के अंतर्गत पर्यटन अधोसंरचना विकसित कर, ग्रामीण, साहसिक व ईको पर्यटन के क्षेत्रों में आजीविका व रोजगार के अवसर सृजित कर नए व ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विविधिकरण पर बल दिया जाएगा। इसी प्रकार, जलापूर्ति, मल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा कौशल उन्नयन, विज्ञापन व विपणन इत्यादि जैसी सेवाओं को शुरू करने तथा समुदाय आधारित पर्यटन गतिविधियों के लिये प्रोत्साहन आधारित तंत्र जैसे अभिनव मॉडल को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना सैलानियों की सन्तुष्टि बढ़ाएगी तथा राज्य में बार-बार आने को प्रोत्साहित करेगी। यह हिमालयी राज्यों के लिए दीर्घकालिक पर्यटन का सबसे बेहतर आदर्श होगा।

परियोजना में कठोर एवं लचीले दोनों संघटक होंगे तथा शहरों का सौन्दर्यीकरण, अनछुए क्षेत्रों का विकास, स्मारक भवनों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण, साहसिक अधोसंरचना का विकास, समुदायिक सहभागिता से ईको ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा और रोज़गार सृजन गतिविधियों का समावेश होगा। परियोजना के तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिये पर्यटन व संबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह परियोजना राज्य के 12 जिलों में 324 स्थलों का अध्ययन तथा 90,000 सैलानियों के सुझाव प्राप्त कर विस्तृत बेसलाइन डाटा तथा हिमालयी राज्यों के लिए दीर्घकालिक पर्यटन के आधार पर तैयार की गई है।

भारत सरकार के केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए परियोजना को प्रोत्साहन दिया है।

आर्थिक मामले विभाग प्रदेश में एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 600 करोड़ रुपये की परियोजना के कार्य व प्रगति से संतुष्ट है।

'मेरे स्कूल से निकले मोती' शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में शिक्षा विभाग में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय 1 अप्रैल, 2018 से 1900 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने डॉ. राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की। इससे 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के प्रदेश में छः मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो गए हैं।

मंत्रिमण्डल ने मैरिट आधार पर प्रवेश प्रदान करने के उद्देश्य से एनआरआई सीटों के कोटे को सीमित करने का फैसला लिया।

बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खण्ड स्तर पर लेखाकार एवं सहायक स्टॉफ के 100 पद तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के 30 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने राजकीय पाठशालाओं से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों, जिन्होंने अपने जीवन में पहचान बनाई है, को सम्मान प्रदान करने के लिए 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र' के अनुरूप 'अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती' शुरू करने के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थियों का नाम सम्बन्धित पाठशाला के डिस्प्ले बोर्ड में अकिंत किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने अन्य राज्यों से कान्ट्रेक्ट कैरिएज के शुल्क ढांचे के युक्तिकरण के लिए मोटर वाहन अधिनियम,1999 के नियम-69ए में संशोधन को मंज़ूरी प्रदान की।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार पर हो कड़ी कार्रवाई:डॉ.किरिट

शिमला/शैल। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में अपने अध्ययन दौरे के दौरान मुख्य सचिव तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता संसदीय समिति के अध्यक्ष डा. किरिट पी. सोलंकी ने की। समिति

के अन्य सदस्यों में डा. रामचरितर निशाद, डा. पी.के. बीजू, अन्जु बाला, राम कुमार वर्मा, डी. आर. शेखर, शमशेर सिंह दुलो, प्रो. सीताराम अजमीरा नायक, प्रतिमा मण्डल, मुकेश कुमार तथा एल. सिंगसन भी बैठक में मौजूद रहे।

डा. किरिट पी. सोलंकी ने हिमाचल प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात कही और इन लोगों के साथ अत्याचारों के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि देशभर में अत्याचार होते हैं, लेकिन इनकी सही रिपोर्टिंग नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि मामले रफा-दफा नहीं किए जाने चाहिए और न ही किसी प्रकार के दबाव के चलते इनमें समझौता किया जाना चाहिए और शीघ्र न्याय के लिये फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति निजी अधिवक्ता की सेवाएं भी ले सकता है।

उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिये धन का उपयुक्त आवंटन किया जाना चाहिए और पूरी राशि को इनके कल्याण के लिये खर्च किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में इन वर्गों के कल्याण के लिये किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताया।

मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने इस अवसर कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिये अनेक योजनाएं व कार्यक्रम प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए हैं। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 25.19 प्रतिशत जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.88 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत राज्य बजट का 25.19 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के लिये 1586.97 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। इसी प्रकार, जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत 2017-18 के दौरान 65 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

मुख्य सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से इन वर्गों के उत्थान के लिये अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें स्वरोजगार योजना, हिमस्वावलंबन योजना, शिक्षा ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, हस्तशिल्प योजना, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा 810 लाभार्थियों को 374.54 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के जनजातीय जिलों में यहां तक कि दो बच्चों के लिये भी स्कूल और अध्यापक उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजाए आवासीय सुविधा प्रदान करने के गांव के समीप स्कूल खोले हैं ताकि बच्चे अपने अभिभावकों के संरक्षण में रह सकें। उन्होंने कहा कि जनजातीय जिला लाहौल-स्पिति तथा चम्बा के पांगी में लोगों को स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने के लिये निःशुल्क टैलीमेडिसिन सुविधा प्रदान की गई है और जल्द ही यह सुविधा राज्य के 20 और स्थानों में प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 से 25 हजार लोगों पर स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 80000 लोगों पर है। उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह के लिये 50000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इन वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में निर्धारित आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित

शिमला/शैल। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने व्यक्तिगत तौर पर विभिन्न श्रेणियों तथा हिमाचल प्रदेश के संस्थानों से पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों, अस्पतालों, होटलों/ रिज़ॉर्ट, रेस्तरां, उद्योगों, पाठशालाओं के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालय परिसरों, आवास/आवासीय कल्याण समिति, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन इत्यादि विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रदान किए जाएंगे।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थानों का पर्यावरण संरक्षण तथा राज्य के सत्त विकास में योगदान के लिए प्रयासों की पहचान करना है। पुरस्कार के लिए आवेदक य. एस. क्लब शिमला के समीप पर्यावरण भवन स्थित पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 17 जून, 2018 तक आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पहला पुरस्कार 50000 रुपये तथा एक ट्रॉफी और प्रमाणपत्र जबकि दूसरा पुरस्कार 25000 रुपये के साथ ट्रॉफी और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध है। विज्ञापन तथा पुरस्कार के लिए आवेदन प्रपत्र विभाग की वैबसाईट www.desthp.nic.in पर उपलब्ध है।

राज्य सरकार सक्षम व्यक्तियों के कल्याण के लिये समर्पित:सैजल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति समाज का अभिन्न हिस्सा है और समाज

के विकास में उनका बहुत योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन लोगों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

विकलांगता पहचान पत्र ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की जाती है, को विभाग द्वारा जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से कंप्यूटीकृत विकलांगता पहचान पत्र जारी किये जा रहे हैं जिसके आधार पर विकलांग व्यक्ति सरकार द्वारा संचालित विकलांगों के कल्याणार्थ योजनाओं का लाभ उठाने के लिये पात्र बन जाते हैं। 31.03.2018 तक विभाग द्वारा 89327 पहचान पत्र जारी किए गये हैं।

छात्रवृति: विशेष रूप से सक्षम बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने व वितीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे विकलांग छात्र जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत अथवा अधिक हो को बिना किसी आय सीमा के 650 रुपये से लेकर 3750 रुपये प्रतिमाह तक की छात्रवृति प्रदान की जा रही है।

स्वरोजगार सहायता: 40 प्रतिशत या इस से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को लघु औद्योगिक इकाईयां जैसे की चाय, दर्जी, छोटी वाहन, ब्यूटी पार्लर इत्यादि की दुकान के लिए अल्पसंख्यक वित्त एंव विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिस पर विभाग द्वारा 10000 रुपये या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत का उपदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण-चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकलांगजन को चयनित व्यवसायों मे निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसके लिये प्रशिक्षणार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृति भी दी जा रही है। विवाह अनुदान-स्वेच्छा से विकलांग लड़के अथवा लड़की से विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये व 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विशेष योग्यता वाले बच्चों की शिक्षा का भी सरकार समुचित प्रबंध कर ही है।

शत्रु द्वारा किया गया स्नेहिल व्यवहार भी दोषयुक्त समझना चाहिए।.....चाणक्य

सम्पादकीय

क्या अप्रसांगिक हो रही है आईएएस व्यवस्था

भारत सरकार ने पैट्रोलियम, वित्त, आर्थिक मामले कृषि और स्टील आदि कुछ मन्त्रालयों में संयुक्त सचिवों के दस पद भरने के लिये निजिक्षेत्र में काम कर रहे लोगों से आवेदन मांगे हैं। यह पद तीन वर्ष के अनुबन्ध पर भरे जायेंगे और अनुबन्ध की अवधि दो वर्ष बढ़ाई जा सकती है। निजिक्षेत्र से अनुभवी लोगों को पहले भी ऐसी एक-आध नियुक्तियां दी जाती रही है। बल्कि भारत सरकार में सचिव स्तर तक ऐसे लोग सेवाएं दे चुके हैं। पैट्रोलियम और वित्त मंत्रालयों में निजिक्षेत्र से आये लोग सचिव रह चुके हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जब भी लाया गया तो उन्हें स्थायी नियुक्तियां दी गयी थी। अनुबन्ध के आधार पर ऐसी नियुक्तियों का प्रयोग पहली बार हो रहा है। इन लोगों का चयन संघ लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। एक साथ दस लोगों को विभिन्न मन्त्रालयों में संयुक्त सचिव के पद पर तीन वर्ष के अनुबन्ध पर नियुक्ति किये जाने से स्वभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में कोई नियोजित प्रयोग करने जा रही है। यदि यह प्रयोग सरकार के अघोषित लक्ष्यों की पूर्ति के मानदण्ड पर सफल रहता है तो क्या आईएएस की जगह कोई नयी प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल सरकार के इस फैसले के बाद उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि इस फैलसे से पहले यह भी एक फैसला चर्चा में रहा है कि अब आईएएस को लोकसेवा आयोग के चयन पर ही राज्यों का आबंटन नही हो जायेगा बल्कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जो परिणाम रहेगा उसके आधार पर आवंटन किया जायेगा।

सरकार के इन फैसलों से पहली चीज तो यह उभरती है कि सरकार आईएएस की मौजूदा व्यवस्था को उपयोगी नही मान रही है। इसके विकल्प के रूप में कुछ नया लाना चाहती है। इस समय जो लोग इन पदो पर अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त होंगे वह निश्चित तौर पर किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी या किसी बड़े औद्यौगिक घराने में अपनी सेवायें दे रहे होंगे। क्योंकि इन पदों के लिये योग्यता की शर्त यही है कि वह इसके लिये अपने को Talented मानते हों। आईएएस बनने के लिये शैक्षणिक योग्यता आज भी स्नातक ही है चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से स्नातक हो। आईएएस हो जाने के बाद सोलह वर्ष के कार्यकाल के बाद संयुक्त सचिव बन जाता है लेकिन निजिक्षेत्र से आने वाले का न्यूनतम अनुभव कितने वर्ष का होगा यह स्पष्ट नही किया गया है। इसका आकलन यह चयन कमेटी ही करेगी। आईएएस एक प्रशासनिक सेवा है उसका प्रशिक्षण प्रशासन चलाने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रशासन में सबसे निचले कर्मचारी से लेकर शीर्ष अधिकारी तक सबके दायरे अधिकार और कर्तव्य पूरी तरह परिभाषित हैं। हम एक वेल्फेयर स्टेट हैं जहां हर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सबसे लोक कल्याण के हित में काम करना अपेक्षित रहता है। इसमें Public interest '' सर्वोपरि रहता है। इसीलिये सरकार में हर अधिकारी /कर्मचारी को उसकी सेवानिवृति उसे सेवा की सुरक्षा मिली हुई है।

इसके विपरीत निजिक्षेत्र में यह नही है कि उसके अधिकारी/कर्मचारी को एक निश्चित अवधि तक सेवाकाल की सुरक्षा नही है। निजिक्षेत्र में वेल्फेयर स्टेट की अवधारणा भी लागू नही होती है। वहां तो नौकर को मालिक वेल्फेयर की पूर्ति करनी है। उसे मालिक को अधिक से अधिक लाभ कमाकर देना है। निजिक्षेत्र लाभ की अवधारणा पर चलता है जबकि सरकार वेल्फेयर की। सबका हित- सबका कल्याण, सबका विकास यह वेलफेयर स्टेट के मूल उद्देश्य हैं। इसमें लाभ से पहले कल्याण रहता है लेकिन निजिक्षेत्र में यह कल्याण और लाभ एक व्यक्ति, एक कंपनी या एक औद्योगिक घराने तक ही सीमित रहता है। ऐसे में जिस व्यक्ति को तीन या पांच वर्ष के अनुबन्ध पर नियुक्त किया जायेगा उसे प्रशासन की सारी बारिकियां समझने में समय लगेगा। बल्कि वह तो जिस भी संस्थान से पूर्व में जुड़ा रहा होगा उसी कार्य संस्कृति से प्रभावित रहेगा और उन्ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा। संयुक्त सचिव कृषि के पद पर बैठकर वह किसान के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करवाने में नीति के स्तर पर क्या योगदान दे पायेगा। वह किसान का कर्जा माफ किये जाने की वकालत कैसे कर पायेगा वित्त और आर्थिक मामलों का संयुक्त सचिव क्या एनपीए की व्यवस्था को समाप्त करने की राय दे पायेगा। क्या वह बहुराष्ट्रीय कंपनीयों के हितों से विपरीत जा पायेगा। यदि कोई अंबानी- अदानी औद्योगिक घरानों से जुड़ा व्यक्ति पैट्रोलियम या रक्षा उत्पादन में संयुक्त सचिव हो जाता है तो क्या वह पैट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत करेगा। रक्षा उत्पादन में क्या वह शफेल डील पर सवाल उठा पायेगा? इसलिये सरकार को यह प्रयोग करने से पहले इसके निहित उद्देश्यों की जानकारी जनता के सामने रखनी होगी।

यदि सरकार को लगता है कि आईएएस व्यवस्था अप्रसांगिक होती जा रही है और उसे हर मन्त्रालय में विषय विशेषज्ञ चाहिये तो उसे आईएएस व्यवस्था में अलग से सुधार करने चाहिये। जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञ चाहिये उनके लिये आईएएस मे ही पोस्टल, राजस्व और आडिट की तर्ज पर अलग सेवाओं की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिये शैक्षणिक योग्यताएं भी स्नातक से बढ़ाकर विषय विशेषज्ञता की तय करनी होंगी, अन्यथा जो प्रयोग अब किया जाने लगा है उससे यही संदेश जायेगा कि सरकार संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों को कुछ प्रमुख पदों पर बैठाने की जुगाड़ भिड़ा रही है।

बहुत कुछ बता गए जाते जाते

लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठाता है तो वो अपनी जीवन लीला भले ही समाप्त कर लेता है लेकिन जाते जाते कई सवालों को जन्म दे जाता है। लेकिन साथ ही कई उत्तर भी दे जाता है समाज को, जैसे कि अपने ईश्वर को किसी अन्य इंसान में मत ढूंढो क्योंकि ईश्वर तो एक ही है जो हम सबके भीतर ही है।

''डॉ नीलम महेंद्र''

भैयूजी महाराज जैसा व्यक्तित्व जिसे राष्ट्र संत की उपाधि दी गई हो, जिसके पास देश भर में लाखों अनुयायीयों की भीड़ हो, इस भीड़ में आम लोगों से लेकर खास शख्सियतें भी शामिल हों, इन शख्सियतों में केवल फिल्म जगत या व्यापार जगत ही नहीं सरकार बनाने वाले राजनैतिक दल से लेकर विपक्षी दलों तक के नेता शामिल हों, इससे अधिक क्या कहा जाए कि इनसे सम्पर्क रखने वाली शख्सियतों में देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हों, लेकिन वो खुद संतों की सूची में अपनी सबसे जुदा शख्सियत रखता था।

जी हाँ भैयू जी महाराज, वो शख्स, जो आध्यात्म और संतों की एक नई परिभाषा गढ़ने निकला था,

कदाचित इसीलिए वो खुद को एक गृहस्थ भी और एक संत भी कहने की हिम्मत रखता था,

शायद इसीलिए वो मर्सिडीज जैसी गाड़ियों से परहेज नहीं करता था,

और रोलेक्स जैसी घड़ियों के लिए अपने प्रेम को छुपाता भी नहीं था,

क्योंकि उसकी परिभाषा में आध्यात्म की राह कर्म से विमुक्त होकर अर्थात् सन्यास से नहीं अपितु कर्मयोगी बनकर यानी कर्म से होकर निकलती थी,

शायद इसीलिए जब इस शख्स से उसके आध्यात्मिक कार्यों की बात की जाती थी तो वो अपने सामाजिक कार्यों की बात करता था।

वो ईश्वर को प्रकृति में, प्रकृति को जीवन में और जीवन को पेड़ों में देखता था।

शायद इसीलिए उसने लगभग 18 लाख पेड़ लगवाने का श्रेय अपने नाम किया।

शायद इसीलिए वो अपने हर शिष्य से गुरु दक्षिणा में एक पेड़ लगवाता था, शायद इसीलिए वो ईश्वर को जीवन दायिनी जल में देखता था।

शायद इसीलिए वो अपने आध्यात्म की प्यास जगहों जगहों अनेकों तालाब खुदवाकर बुझाता था।

वो ईश्वर को इंसानों में देखने की कोशिश करता था शायद इसीलिए उसने महाराष्ट्र के पंडरपुर में रहने वाली वेश्याओं के 51 बच्चों को पिता के रूप में अपना नाम दिया था

शायद आध्यात्म उसके लिए वो बन्धन नहीं था जो उसे सांसारिक गतिविधियों से दूर करे बल्कि ये वो शक्ति थी जो उसे जिंदगी जी भर के जीने की आजादी देती थी,

शायद इसीलिए वो घुड़सवारी भी करता था तलवारबाजी भी करता था, मॉडलिंग भी करता था और एक गृहस्थ संत बनके देश भर में अपने लाखों अनुयायी भी बना लेता था।

वो सबसे पहले चर्चा में तब आता है जब अन्ना हजारे का अनशन खत्म करने के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार उन्हें अपना दूत बनाकर भेजती है और अन्ना उनके हाथों से जूस पीकर अपना अनशन समाप्त करते हैं।

प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सदभावना उपवास पर बैठते हैं तो उनका उपवास खुलवाने के लिए इन्हें ही आमंत्रित किया जाता है।

वो उस मुकाम को हासिल करता है जब मध्य प्रदेश सरकार उसे राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करती है, हालांकि वो उसे ठुकराने का जज्बा भी रखता था।

लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठाता है तो वो अपनी जीवन लीला भले ही समाप्त कर लेता है लेकिन जाते जाते कई सवालों को जन्म दे जाता है।

लेकिन साथ ही कई उत्तर भी दे जाता है समाज को जैसे कि अपने ईश्वर को किसी अन्य इंसान में मत ढूंढो क्योंकि ईश्वर तो एक ही है जो हम सबके भीतर ही है।

वो लोगों को यह संदेश दे जाता है कि दूसरों को शांति का संदेश देने वाला खुद भीतर से अशांत भी हो सकता है।

वो यह जतला जाता है कि दुनिया पर विजय पाने वाला कैसे अपनों से ही हार जाता है।

अपने इस कदम से वह यह सोचने को मजबूर कर जाता है कि वर्तमान समाज में जिन्हें लोग संत मानकर, उन्हें ईश्वर के करीब जानकर उन पर ईश्वर तुल्य श्रद्धा रखते हैं क्या वे वाकई ईश्वर के करीब होते हैं?

वे यह जता जाते हैं कि जो लोग एक ऐसे व्यक्ति के पास अपनी उलझनों के जवाब तलाशते चले आते हैं क्या वे इस बात को समझ पाते हैं कि कुछ उलझनें उसकी भी होती होंगी, जिनके उत्तर वो किससे पूछे खुद उसको भी नहीं पता होता।

हाँ यह बात सही है कि ऐसे व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं लेकिन यह भी तो सच है कि आखिर ये इंसान ही होते हैं।

हाँ ये बात सही है कि इनमें एक आम आदमी से ज्यादा गुण होते हैं लेकिन यह भी तो सच है कि कमजोरियां इनकी भी होती हैं।

लेकिन फिर भी ये समाज में अपने लिये एक खास स्थान बनाने में इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि अपनी कमजोरियों को ये अपनी प्रतिभा से छुपा लेते हैं और अपने अनुयायियों की संख्या को अपनी ताकत बनाने में कामयाब हो जाते हैं।

चूंकि हमारे देश के राजनैतिक दल इनकी इस ताकत को अपने वोटों में बदलना जानते हैं।

क्या इस तथ्य को नकारा जा सकता है कि ऐसे व्यक्तियों की लोकप्रियता बढ़ाने में राजनैतिक दलों का योगदान नहीं होता?

क्या अपनी लोकप्रियता के लिए ऐसे ''संत'' और वोटों के लिए हमारे राजनेता एक दूसरे के पूरक नहीं बन जाते?

नेताओं और संतों की यह जुगलबंदी हमारे समाज को क्या संदेश देती है?

इन समीकरणों के साथ भले ही धर्म का उपयोग करके राजनीति जीत जाती हो लेकिन नैतिकता हार जाती है।

तारीखों में दर्ज हुई किम–ट्रंप मुलाकात

ट्रंप और किम की शिखर बैठक ने उत्तर कोरिया को यह मौका दे दिया कि वह अपना परमाणु कार्य खत्म कर अपने देश को गरीबी और बदहाली से उबारे। ट्रंप ने भी इसकी सुरक्षा की गारंटी की बात कह दी है परन्तु उस पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। रोचक यह भी है कि किम और ट्रंप जो एक–दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे थे साथ ही शब्दों के बाण और धमकियां जहां दोनों ओर से अनवरत जारी थीं वहीं सिंगापुर में दोनों गहरी सूझबूझ दिखा रहे थे।

वास्तव में रूस और चीन जैसे देश को छोड़ दिया जाये तो पूरी दुनिया में उत्तर कोरिया का कोई बड़ा हितैषी नज़र नहीं आता। इस परिप्रेक्ष्य में दृष्टि गड़ा के देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनकी मुलाकात ने उत्तर कोरिया को यह अवसर दे दिया है कि वह न केवल अपना निर्वासन खत्म करे बल्कि अन्तरराष्ट्रीय बिरादरी से जुड़ने के अवसर का लाभ भी उठाये। बरसों की तनातनी मात्र एक मुलाकात से दुनिया के लिये राहत की सांस बन जायेगी ऐसी अवधारणा इतिहास में शायद ही हो। डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के किम जोंग ने सिंगापुर में जो किया वह विश्व इतिहास के पन्ने पर आम इतिहास तो नहीं कहा जायेगा। इसी वार्ता ने दोनों देशों के 68 बरस की शत्रुता का अंत कर दिया। गौरतलब है 1950 से 1953 के उत्तर व दक्षिण कोरियाई युद्ध के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों की यह पहली मुलाकात थी। सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर स्थित कैपिला होटल में 50 मिनट की ऐतिहासिक शिखर वार्ता जिस राह को अख्तियार किया वह कहीं न कहीं तीसरे विश्व युद्ध के आगाज का भी अन्त कहा जा सकता है। खास यह भी है कि आइजन हॉवर (1953) से लेकर बराक ओबामा (2016) तक 11 राष्ट्रपतियों ने उत्तर कोरिया से सम्बंध सुधारने की कोशिश की लेकिन सफलता डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आई।

कई अवसर ऐसे भी देखे गये जब मनोवैज्ञानिक संतुलन के लिये ट्रंप ने किम के बांह और पीठ पर हाथ रखा, एक बार किम ने भी ऐसा किया। ट्रंप के हावभाव ने यह भी एहसास कराया कि अमेरिका ताकत वाला देश है।

71 वर्षीय ट्रंप और 34 वर्षीय किम के बीच वाकई में अच्छी कैमिस्ट्री देखने को मिली। उत्तर कोरिया में कम उम्र के लोगों को बड़ों से पहले स्थल पर पहुंचना होता है इसका निर्वहन करते हुए किम 7 मिनट पहले से वहां उपलब्ध थे। चन्द माह पहले दोनों देश शत्रुता के चरम बिन्दु पर थे और युद्ध के कगार पर पहुंच गये थे अब उनके बीच शान्ति का पर्व वाकई अद्भुत है। अमेरिका की आंखों में चुभने वाला किम अब ट्रंप के लिये प्रतिभाशाली हो गया है और व्हाइट हाउस में बुलाने लायक भी। दरअसल वैश्विक फलक पर कूटनीति सीधे राह पर नहीं चलती बल्कि यह अपना टेढ़ा–मेढ़ा स्वरूप भी अख्तियार करती है। उत्तर कोरिया भले ही राह से भटक कर साल 2006 से लेकर अब तक 6 परमाणु परीक्षण समेत कई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया के लिये किरकिरी बना हो पर अमेरिका से सम्बध जुड़ने के बाद सभी इसके घातक सिद्धांत से कमोबेश मुक्त महसूस कर रहे होंगे। इसमें सबसे ज्यादा दक्षिण कोरिया और जापान खुश होंगे। गौरतलब है कि ट्रंप ने मुलाकात से पहले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून से फोन पर बातचीत की थी। वार्ता के बाद ट्रंप ने जापान और चीन के प्रयासों को लेकर उनकी सराहना भी की थी।

फिलहाल ट्रंप और किम की मुलाकात से दुनिया चैन की सांस ले सकती है मगर उत्तर कोरिया को वार्ता के लिये डोनाल्ड ट्रंप के समीप पहुंचाने हेतु चीन और रूस की पर्दे के पीछे की भूमिका को कमतर नहीं आंका जा सकता। वार्ता से पहले किम ने दो बार चीन की यात्रा की जाहिर है कि चीन की सीख उसे काम आई होगी। किम बीते कुछ महीनों में जिस तर्ज पर अपने को परिवर्तित नेता के रूप में परोसने की कोशिश की वह भी वार्ता की सफलता के लिये अहम सिद्ध हुआ। इस मुलाकात के वैश्विक पटल पर कई मायने निकाले जा सकते हैं परन्तु भारत के लिये उत्तर कोरिया एक नया बाजार हो सकता है और कोरियाई प्रायद्वीप में वह अपनी वृहद नीति को तत्परता से आगे बढ़ा सकता है। जाहिर है यहां से अब आगे की कवायद कूटनीतिक व आर्थिक हितों को साधने की होगी।

– सुशील कुमार सिंह –

कोरियाई प्रायद्वीप अब एक साथ अमेरिका, चीन व जापान जैसे विश्व शक्तियों की कूटनीतिक गतिविधियों का बड़ा केन्द्र हो सकता है। ऐसे में

भारत को भी अपने हितों को लेकर कुछ हद तक सतर्क रहना होगा। हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में देशों की आक्रामक नीतियां रही हैं। अमेरिका और कोरियाई द्वीप समेत जापान के साथ यदि चीन का परिप्रेक्ष्य भी सकारात्मक होता है तो इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं पर सच्चाई यह भी है कि चीन को छोड़ सभी देशों से भारत के रिश्ते अच्छे हैं। रिश्ते तो चीन से भी अच्छे हैं ऐसे में इसकी सम्भावना कम है परन्तु फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। भारत 2016 में चीन के बाद उत्तर कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार देश था। वह बड़े पैमाने पर यहां खाद्यान्न की आपूर्ति भी करता रहा। विदेश नीति के जानकार यह मानते हैं कि ट्रंप और किम की मुलाकात के बाद यहां की फिजा बदलेगी जरूर। इसमें दक्षिण कोरिया की भी भूमिका अहम मानी जा सकती है। गौरतलब है कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून पहले से ही भारत आने की तैयारी में है लेकिन उत्तर कोरिया में मचे घमासान के बीच यह सम्भव नहीं हुआ। सम्भव है कि अगले महीने जुलाई में उनकी यात्रा सम्पन्न हो।

किम जोंग ने भी कहा है कि दुनिया अब नया बदलाव देखेगी। ट्रंप और किम जोंग ने पनपते विश्व अशान्ति को शान्त कर दिया है परन्तु आतंकवाद से दुनिया अभी भी त्रस्त है। भारत के लिये आतंकवाद बड़ा पहलू रहा है। यही कारण है कि ट्रंप की निगाहें पाकिस्तान पर टेढ़ी ही हैं।

भले ही उन्होंने पाकिस्तान को धूर्त देश घोषित किया हो पर आतंक को लेकर अभी अढ़ाई कोस भी नहीं चल सके हैं। सम्भव है कि उत्तर कोरिया से ध्यान हटाकर अब ट्रंप पाकिस्तान पर निगाहें लगायें। यदि पाक आयातित आतंक से भारत को राहत मिलती है तो यह उसकी बड़ी सफलता होगी और काफी हद तक चीन को भी सबक मिलेगा। सभी जानते हैं कि हर मौके पर चीन पाकिस्तान के साथ होता है। फिलहाल सिंगापुर में इस साल की सबसे जबरदस्त तस्वीर तब देखने को मिली जब ट्रंप और किम टेबल टॉक कर रहे थे और दोस्ती की मिसाल के साथ इतिहास गढ़ रहे थे। वार्ता के दो दौर थे और इसकी गम्भीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक समस्या का हल इस वार्ता को करार दिया। परमाणु बम पर बटन दबाने की धमकी देने वाले दोनों नेता आपस में मुस्कुरा और खिलखिला रहे थे।

कह सकते हैं कि पहली मुलाकात का आगाज यह है तो किम द्वारा किये गये वायदे जिसे लेकर ट्रंप को पूरा विश्वास है कि निभाया जायेगा उस पर किम खरा उतरता है तो अमेरिका का उत्तर कोरिया के प्रति आने वाले दिनों में अंदाज कहीं अधिक सकारात्मक और अलग दिखेगा। सबके बाद दो टूक यह है कि 12 जून, 2018 अन्तरराष्ट्रीय बिरादरी में एक ऐसी तिथि है जिसका मंथन कई अवसरों पर समय के साथ किया जाता रहेगा। (देशबन्धु से साभार)

महाराणा प्रताप बुन्दलों के गौरव रहे हैं

युग पुरूष महाराणा प्रताप मन, वचन व कर्म से मातृभूमि की रक्षा के लिये समर्पित रहे। इनका इतिहास आन, बान, शान और वीरता के लिये बीता है। महाराणा प्रताप बुन्देला गौरव की मशाल राजस्थान में रहे हैं। ज्येष्ट तृतीय शुदि: को अर्थात् मई सन् 1550 को अपने ननिहाल के गृह पैदा हुये थे। माता जयवंता व पिता उदय सिंह महाराज रहे। ओरछा में बुन्देला राज्य की स्थापना करने वाले रूद्र प्रताप के वंशज थे। राणा प्रताप ने बाल्यकाल से अस्त्र–शस्त्र, घुड़सवारी और राज्य संचालन की दक्षता पा ली थी। इनके पिता ने मुगलों की विस्तार नीति के कारण चितौड़ को त्याग कर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में सुरक्षा की दृष्टि से शरण ली थी। इसी के परिणामस्वरूप उदय नगर का जन्म हुआ। यह वह समय था जब मुंगल अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। प्रताप और भाई ने घर की पूंजी लगा करके थोड़ी सेना तैयार की और बुन्देल को मुगलों से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया था। राणा प्रताप ने कई कठिनाईयों एवं कष्टों को सहते हुये अकबर बादशाह की अंश मात्र भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन का धैर्य, आत्म विश्वास और अनवरत प्रयत्न विश्व इतिहास में एक अनुकरणीय उदाहरण है और अपने 25 वषीय शासनकाल में अपने नाम को वास्तविक रूप में सार्थक किया था।

राणा प्रताप का मेवाड़ राज्य का युद्ध मुगल साम्राज्य से अंत तक रहा हैं। इसे भारत के इतिहास में गौरव पूर्ण माना जाता है। यह सिसोदिया वंश से सम्बधिंत थे। पिता की मृत्यु के बाद मेवाड राज सिंहासन पर 28 फरबरी, 1572 को बैठे थे। चितौड़ उस समय मुगल बादशाहों की आंख का मुख्य केन्द्र रहा है। मुगलों का उस समय सारे उत्तर भारत में आधिपत्य बढ़ता जा रहा था। इस कारण राणा प्रताप ने अपनी राजधानी कुम्भल को कुछ समय हेतू अस्थाई बनाई। यह चारों ओर से पहाड़ियों से छिपी हुई व सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित थी। गुजरात पर अकबर ने अपना राज्य स्थापित किया। उस के बाद राणा के पास अपना एक विश्वासपात्र भेजा था। राणा ने उस का खूब आदर सत्कार किया। अपने चौदह वर्ष के बेटे को उस के साथ आगरा के दरबार में भेंट देने हेतू भेजा, ताकि कुछ समय के लिये राणा अपने संगठन को और मजबूत कर सकें। कुछ समय के लिये युद्ध टाला जा सके। मुगल सम्राट मेवाड़ को समाप्त करना चाहता था। राणा उस की रक्षा में डटे थे। राज

सिंहांसन पर बैठने के बाद राणा प्रताप ने मेवाड़ की रक्षा का प्रण लिया था। जब तक इसको स्वतंत्र नहीं कराया जायेगा मैं राजसी ठाठ बाट में नहीं रहूंगा। इसी कारण सारी राजसी वस्तुओं को त्याग कर जंगलों की शरण ली और मेवाड को संगठित करने के लिये जीवन लगाया। सेना को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। सम्राट अकबर ने प्रलोभन भी दिये परन्तु राणा ने किसी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। अरावली की पहाड़ियों में आदिवासियों को संगठित किया और युद्ध करते रहे। मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस के बाद गुरिल्ला युद्ध से मुगलों को परास्त किया। लगभग 24 वर्ष तक राणा प्रताप युद्ध में रहे थे। राणा प्रताप की यह अपनी कूटनीति और कार्यनीति थी। इसके बाद राणा प्रताप ने मुगलों की हर चौकी व थाने जो मुगलों के अधीन रहे। उन राजाओं को लूटा व अपार धन एकत्रित किया। इस का वर्णन लाल कवि के नाम से विख्यात गौरे लाल पुरोहित के प्रबन्ध काव्य में छत्रसाल के युद्धों के वर्णन में मिलता है।

महाराणा प्रताप को कुछ राजाओं ने स्वंतत्र राजा मान लिया था। इस के बाद ही राणा ने कालिंजर दुर्ग को विजय किया। साथ पन्ना को राजधानी बनाया था। जहां उनके गुरू प्राण नाथ जी जामनगर गुजरात से आकर के बसे थे। उस समय निरगुनिया भक्ति का जोर था। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में प्राण नाथ ने वेद, कुरान के उद्धरणों बारे प्रकाश डाला है। हिन्दुओं और मुस्लमानों के धर्मो में बुनियादी अंतर नहीं बताया है। उनके परनाभी सम्प्रदाय में मांस निशिद्ध और मूर्तिपूजा, जाति प्रथा तथा पुरोहितवाद को निरर्थक कहा है। महान संत प्राण नाथ की मौत पन्ना में सन् 1654 को इुई। वही इनकी समाधि है। हर साल वहां एक मेले का आयोजन होता है। साथ प्राण नाथ जी ने यहां हीरे होने का पता भी दिया था। इन का जन्म खेम जी के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। राणा प्रताप ने अपने समय में अकबर के साथ कोई समझौता नहीं किया। जब अकबर अजमेर आया और मान सिंह को अपना मुख्य सेनापति बनाया।

जून 21,1576, को हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इतिहासकारों का कहना है वहां पर एक प्रकार से खून की मानो होली खेली गई हो। राणा प्रताप स्वतन्त्रता की रक्षा हेतू अंत तक डटे रहे, दूसरी ओर मुगलों ने मुलेला गांव में मान सिंह के नेतृत्व में भारी सेना पहले से ही खड़ी कर रखी थी। सबसे पहले मुगलों ने सूर्योदय से पूर्व हमला बोला। राणा ने अपनी सेना को ललकारा कि शत्रु पर टूट पड़ो। भंयकर युद्ध हुआ, प्रताप चारों ओर मान सिंह को ढूढ़ रहे थे। कहते हैं वे एक हाथी पर सवार हो कर मध्य में था। राणा ने उस पर हमला किया। इस में महावत सामने आ गया। महावत मारा गया और मान सिंह एक हौद में छिप गया। हाथी वापिस हुआ तो उस ने अपनी ही सेना रौंदी। राणा के शरीर को मुगलों ने असंख्य घावों से जख्मी कर दिया। उनका विजय दिलाने वाला और साथ रहने वाला घोड़ा चेतक बलि की वेदी पर चढ़ गया। उसने मरने से पहले घायल प्रताप को सुरक्षित बाहर निकाल कर अपनी जान दी। इस युद्ध में 14000 हजार राजपूत सैनिक, भील, मीणा आदि मारे गये और हजारों घायल हुये थे। पराजित होने पर राणा प्रताप की कीर्ति पहले से अधिक फैली। इस युद्ध का वर्णन पं. श्याम नारायण पाण्डेय ने अपने काव्य हल्दीघाटी में किया है। सन् 1577 में कुंभनगढ़ पर पुन: अधिकर करने के लिये शहबाजखां को अकबर ने फिर भेजा पर राणा स्वंय रात के समय ही ढ़ोलन गांव चले गये, क्योंकि यह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सुरक्षित रहा। यहां अंत तक राणा जी ने तीन वर्ष संर्घषपूर्ण ढ़ंग से दिन काटे। राणा के विरोध में अकबर ने सन 1584 में आदेश दिया कि इसको बंदी बना करके या मार करके मेरे पास पेश किया जाये। इसी वर्ष फिर राणा जी ने चावण्ड में अपनी राजधानी बनाई और सारे मेवाड़ को सुरखा, सुशासन दिया। इसकी आज भी मेवाड में प्रशंसा की जाती हैं। इतिहासकार 12 मई, 1731 को प्रताप की मृत्यु मानते हैं। मरने से पूर्व राणा ने अपने विश्वासपात्र को बुला कर कहा। सभी आजादी की शपथ लें। मातृभूमि की रक्षा और सेवा में राणा प्रताप ने जीवन न्यौछावर कर दिया। स्वंय राज सिंहासन और फूलों की सेज को त्यागा। प्रलोभन न पा कर देशभक्ति का मार्ग अपनाया था।

सुदर्शन अवस्थी इन्दु

प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा सुधार: जे.पी.नड्डा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर न केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा की उपस्थिति में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर के 250 बिस्तरों वाले अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर के आवासीय खण्ड का लोकार्पण तथा गांव थाई में मेडिकल कॉलेज के परिसर का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया।

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भवन का निर्माण 206 करोड़ रुपये से किया जाएगा, जबकि आवासीय खण्ड के निर्माण पर 1.91 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस अवसर पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इस छठें आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एमबीबीएस के छात्रों के लिए 100 सीटें होंगी। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निकट के लगभग चार जिलों के लोगों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता तथा प्रदेश की सभी मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा आभारी रहेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में क्रांति स्तर पर प्रगति हुई है। पूर्व सरकार ने लोगों को केवल स्वप्न दिखाए तथा खोखले वायदे किए, लेकिन वर्तमान सरकार स्वप्नों को पूरा करने में विश्वास रखती है तथा पांच माह के अल्पकाल

में जमीनी स्तर पर जनता द्वारा परिणामों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि सदैव केन्द्र सरकार के समक्ष प्रदेश के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में विफल रहे है, जबकि भाजपा के सांसदों ने प्रदेश में रेलवे विस्तार, राष्ट्रीय उच्च मार्गों का निर्माण, स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण, आईआईआईटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थान आदि की स्थापना जैसे मुद्दों को लगातार उठाया है तथा केन्द्र ने इन सभी मांगों को स्वीकार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नई सोच के साथ कार्य कर रही है तथा हिमाचल प्रदेश को विकास व समृद्धता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नई पहलों पर कार्य आरम्भ कर दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में छह तथा निजी क्षेत्र में एक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के खुलने से लगभग 750 चिकित्सक उपलब्ध होंगे, जिससे प्रदेश में विशेषज्ञों व चिकित्सा अधिकारियों की मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हमीरपुर शहर में बस अड्डा, इंडोर स्टेडियम व पार्किंग के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वरिष्ठ नागरिक परिषद् हमीरपुर के भवन के निर्माण के लिए भी सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

केन्द्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पहले से ही तैयार है तथा कम आबादी होने के बावजूद भी प्रदेश को चार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, एम्ज व अन्य विभिन्न चिकित्सा संस्थान प्रदान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के आठ जिलों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है तथा अब किडनी रोगियों को डायलिसिस के लिए पीजीआई चंडीगढ़ वअन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने प्रदेश में आईजीएमसी शिमला व टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी खण्डों, ऊना, सुन्दरनगर, बिलासपुर, मण्डी, घुमारवीं, कांगड़ा, चम्बा तथा नूरपुर में मातृ व शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त मण्डी में टर्शरी कैंसर केन्द्र सहित विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाएं प्रदान की हैं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने देश में महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत कार्यक्रम को आरम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न गंभीर रोगों के ईलाज के लिए 55 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये सालाना का बीमा प्रदान किया जा रहा है।

केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि हमीरपुर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर में मातृ व शिशु स्वास्थ्य केन्द्र तथा नर्सिंग अस्पताल स्थापित करने की मांग पर निकट भविष्य में विचार किया जाएगा।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश को विभिन्न विकासात्मक पहलों के लिए उदार सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सदैव प्रदेश की मांगों पर विचार किया है तथा निकट भविष्य में प्रदेश को और अधिक बड़ी परियोजनाएं प्रदान की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है कि लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में चिकित्सक उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के 272 पद तथा दंत चिकित्सकों के 52 पद भरे गए हैं तथा शीघ्र ही आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद, नर्सों के 1007 तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के 2000 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा 12 स्थानों पर आरम्भ की गई है।

प्रदेश के 5 जिलों को राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत लाया गया: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आरम्भ की गई विभिन्न पहलों, जिनमें कृषि क्षेत्र का विकास व वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, इलैक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम), मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मनरेगा, आयुश्मान भारत, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, मिशन इन्द्रधनुष, स्पेशल डिवेल्पमेंट नीड्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, महात्मा गांधी की 150वह जयन्ती को मनाने के लिए सुझाव, जीएसटी अधिनियम, जैम पोर्टल, भीम ऐप तथा आधार और राज्य स्तर पर उपलब्ध विभिन्न अनटाइड निधि का उपयोग करना शामिल है तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की जा रही प्रगति से अवगत करवाया।

जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए 343.12 करोड़ की केन्द्रीय सहायता अभी लम्बित है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई के अन्तर्गत निधि के लिए वर्ष 2016-17 में 99 सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, हालांकि सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद इस सूची में हिमाचल प्रदेश की एक भी योजना शामिल नही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आग्रह किया है त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एआईबीपी) के अन्तर्गत निधि के लिए 156.31 करोड़ रुपये की मध्यम सिंचाई परियोजना नादौन और 204.51 करोड़ रुपये की फिना सिंह सिंचाई परियोजना को इस सूची में शामिल किया जाए क्योंकि इन योजनाओं में सभी शर्तें पूरी की गई है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत लम्बित निधि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया तथा कहा कि इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं को 99 प्राथमिकता परियोजनाओं की सूची में शामिल किया जाए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए वर्तमान वर्ष में 9 योजनाओं को कार्यान्वित करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए पानी की कमी झेल रहे प्रदेश के पांच जिलों के लिए 4751

करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जल संरक्षण एवं प्रबन्धन का एक प्रस्ताव भी तैयार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से निधि के लिए केन्द्र के समक्ष उठाया है। उन्होंने बताया कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक 10 लाख नए पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य में सहभागिता योजना, मुख्यमंत्री निरोग योजना, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना तथा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जैसी नई याजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से 10 लाख से भी अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं तथा संस्थागत प्रसव की दर 50 से बढ़कर 80 प्रतिशत हुई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के लिए निधि 20:80 के अनुपात से प्रदान जा रही है, जिसमें 20 प्रतिशत केन्द्र तथा 80 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश प्रदान कर रहा है। उन्होंने प्रदेश की कठिन भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर 90:10 के अनुपात के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए आग्रह किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत चम्बा, हमीरपुर, सोलन, शिमला और ऊना जिलों को लाया गया है तथा प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पदों को भरने के प्रयास कर रही है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रदेश सरकार मुख्यालय स्तर से जुड़े पदों का 21 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाएगी। उन्होंने केन्द्र से राज्य के हित में इस निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया ताकि कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों को शीघ्र हासिल किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'स्पेशल डवेल्पमेंट नीड्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स' के अन्तर्गत जिला चम्बा को चिन्हित किया गया है तथा जिला प्रशासन ने जिले के एकीकृत विकास के लिए तीन वर्षीय विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जिसे केन्द्र सरकार को सौंपा गया है।

उन्होंने बैठक में बताया कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान जैम पोर्टल को क्रियाशील बनाया गया है तथा अभी तक 15.88 करोड़ रुपये की वित्तीय लेन-देन किए गए, जबकि भीम ऐप के माध्यम से 658 करोड़ रुपये के लेन-देन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष आधार के माध्यम से 34 योजनाओं के अन्तर्गत 1067 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किए गए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी भी बैठक में उपस्थित थे।

देसी नस्ल की गायों का संरक्षण आवश्यक: वीरेन्द्र कवंर

शिमला/शैल। प्रदेश में देसी नस्ल की गायों के पालन व संरक्षण पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। देसी नस्ल की गायें सदियों से किसानों व उपभोक्ताओं को बेहतर दूध प्रदान करने का स्त्रोत रहीं हैं। लोगों ने सदैव ही देसी नस्ल की गायों पर विश्वास जताया है तथा प्रदेश सरकार राज्य में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से पशुपालन के विकास व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

यह बात पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान व तकनीक विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति द्वारा आयोजित 25वीं बैठक में कही। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में कृषि अनुसंधान व शिक्षा की समीक्षा के साथ-साथ इन प्रदेशों में कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन व वन क्षेत्र से सम्बन्धित स्थल विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण, विचार विमर्श व संस्तुति करना है।

मंत्री ने उच्च जनेटिक गुणवत्ता वाले देसी बैलों के भ्रूण/वीर्य की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तराखण्ड के पशुपालन निदेशक ने आश्वासन दिया कि एक माह के भीतर 4500 लीटर से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले लाल सिन्धी नस्ल के बैलों के वीर्य की 45000 डोज की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रूण की आपूर्ति भी मांग के अनुसार की जाएगी।

कंवर द्वारा साहिवाल नस्ल के वीर्य के मुद्दे को उठाने पर प्रतिक्रिया करते हुए एनडीआरआई करनाल के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि साहिवाल नस्ल के उच्च जनेटिक गुणवत्ता वाले बैलों के वीर्य की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गायों की संख्या को स्तरोन्नत करने के लिए पालमपुर स्थित वीर्य केन्द्र के लिए कुछ समय में बैलों की आपूर्ति भी की जाएगी।

वीरेन्द्र कंवर ने पशु-चारें की कमी की समस्या से निपटने के लिए चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति को संयोजित आहार खण्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्मों में अन्त: प्रजनन की समस्या से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड द्वारा 40 मेढ़े तथा प्रत्येक प्रदेश के लिए रैनबोयलेट व मरीनों नस्ल की 200 भेड़ें आयात करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा तथा केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सीएसकेएच पीकेवी पालमपुर ने ऑप्रेशन गौ- सदनज के लिए एक सत्त मॉडियूल विकसित किया है, जो कि आगामी कार्यवाही के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशमीना उत्पादन के लिए लाहौल-स्पिति के भेड़ पालकों की सुविधा के लिए जम्मू-कश्मीर के लद्दाख से चंगथांगी नस्ल की बकरियां लाई जाएंगी।

शिमला में पुनःसामान्य हुई पानी की सप्लाई

शिमला/शैल। होटल्ज् एड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ नार्थ इंडिया ने पर्यटकों और भ्रमण प्रेमियों के लिहाज से एक अच्छी खबर सुनाई है इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा किये पर्याप्त इंतजामों के साथ अब पानी की सप्लाई पुनः सामान्य हो गई है पर्यटक अब बिना किसी चिंता के हिमाचल राज्य की इस खूबसूरत राजधानी की सैर कर सकते हैं।

पर्यटन जो कि शिमला जैसे पहाड़ी राज्यों में होटल उद्योग के लिये मुख्य आधार है पानी की कमी के दुर्भाग्यपूर्ण हालत की वजह से इस पर बहुत बुरा असर हुआ था, लेकिन ये हालत अब ठीक हो चुके हैं। इसलिये अब इस शहर की यात्रा बिना किसी शंका या चिंता के ही की जा सकती है। क्योंकि मेहमानों की सुविधा का ध्यान रखना हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिये प्रमुख महत्व का विषय है।

संजय सूद, प्रेसिडेंट (एचआरए एन आई) तथा ईसी सदस्य एफएचआरएआई के अनुसार इस उद्योग के हिस्सेदार होने के नाते हम हिमाचल प्रदेश और खासतौर पर शिमला की यात्रा करने वाले पर्यटकों को इस बात के लिए निश्चित भी करना चाहेंगे कि हॉस्पिटलिटी फेटर्निटी पूरी तरह से अपने मेहमानों की सभी जरूरतों तथा आकांक्षाओं का ठीक वैसे ही ध्यान रखने को सभी सुविधाओं के साथ तैयार हैं जैसे पहले रखा जाता था।

सूद ने आगे कहा–इस संद्धर्भ में क्षेत्र का समस्त होटल उद्योग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा कार्यवाहक प्रमुख न्यायधीश संजय करोल के दिल से आभारी हैं कि उन्होने पर्यटकों का ध्यान रखने वाले सभी संस्थानों के लिये पर्याप्त पानी की सप्लाई को सुनिश्चित किया साथ ही हम हमारे दूरदृष्टि रखने वाले मुख्यमंत्री की अगुआई में चलाये जा रहे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अभियान के लिए भी धन्यावाद अदा करते हैं जिसके अन्तर्गत राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विस्तारपूर्वक रणनीतिक रोडमैप बनाया जा रहा है।

एचआरएएनआई होटल उद्योग से जुड़े तथा रेस्त्रां संचालकों का सबसे पुराना शीर्षस्थ संगठन होने के नाते यह महसूस करता है कि शिमला तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रभावित हिस्सों में पर्यटकों के प्रवाह को बनाये रखने के लिये और अधिक प्रयास किये जाने चाहिये। ऐसे केसों में हम मीडिया के प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होते हैं इसलिये हम मीडिया से यह अनुरोध करते हैं कि वे अपनी रिपोर्ट्स द्वारा सामान्य हो चुकी पानी की सप्लाई के बारे में बताएं ताकि राज्य में पर्यटन को फिर से गति मिल सके।

इस स्थिति की तत्कालिक आवश्यकता यही है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मीडिया द्वारा सही, सटीक और रचनात्मक जानकारी का प्रसार किया जाए। सुकून देने वाला मौसम और मंत्रमुग्ध कर देने वाले पहाड़ देश और दुनियाभर के पर्यटकों के स्वागत के इंतजार में है।

होटल्ज् एन्ड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ नार्थ इंडिया (एचआरएएनआई) एफएचआरएआई फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट का एक उत्तरी संगठन है जो 9 उत्तर भारतीय राज्यों के होटल और रेस्टोरेंट उद्योग की शीर्षस्थ संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इस एसोसिएशन की स्थापना 1950 में प्रसिद्ध राय बहादुर एमएस ओबरॉय ने की थी। तब से ही यह संस्थान अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिये असरदार तरीके से काम कर रहा है और राज्य में पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता जा रहा है यह नौ राज्यों में शामिल है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंव कश्मीर, यूपी तथा उत्तराखंड।

पांच माह में ओक ओवर से सचिवालय

.... पृष्ठ 1 का शेष

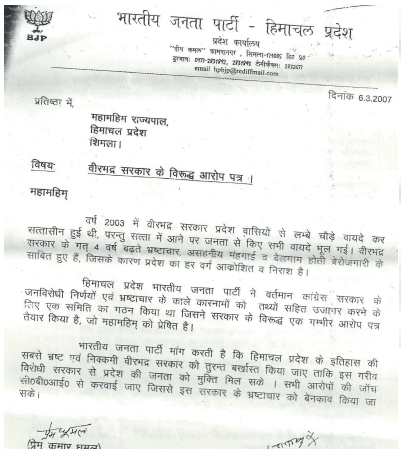

पहुंचे तो क्या इससे मुख्यमन्त्री के अपने ही सचिवालय की कार्यप्रणाली पर आम आदमी का भरोसा बन पायेगा। प्रतिवेदन में की गयी मांग से सहमत होना या न होना प्रतिवेदन का आकलन करने वाले का अपना अधिकार है लेकिन उस प्रतिवेदन पर हुई कारवाई की जानकारी तो प्रतिवेदन देने वाले को मिलनी चाहिये यह उसका अधिकार है। यदि प्रतिवेदन से असहमत हो तो असहमति के आधार जानने का भी प्रतिवेदन देने वाले को अधिकार है लेकिन जब प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री के यहां से कहीं पहुंचे ही नही तो फिर सारी कार्यशैली की नीयत और नीति पर सवाल उठने स्वभाविक हैं। क्योंकि इस प्रतिवेदन में कई बड़े अधिकारियों और नेताओं को लेकर गंभीर आरोप हैं और इससे यही संदेश जाता है कि बड़ो के भ्रष्टाचार पर केवल जनता में भाषण ही दिया जा सकता है उस पर कारवाई नही। ऐसे मे जिन बड़े लोगों से संपर्क करके समर्थन मांगा जा रहा है उन सबके लिये यह एक बड़ा आईना है जिसमें वह सरकार की सही छवि का दर्शन और फिर आकलन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे और कई मामले आने वाले दिनों में सामने आयेंगे।

BJP

भारतीय जनता पार्टी - हिमाचल प्रदेश
प्रदेश कार्यालय
"दीप कमल" कामनानगर, शिमला-171005 हि० प्र०
दूरभाषः 0177-2831892, 2831893 टेलीफैक्सः 2832677
email hpbjp@rediffmail.com

दिनांक 6.3.2007

प्रतिष्ठा में,

महामहिम राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश
शिमला।

विषयः वीरभद्र सरकार के विरूद्ध आरोप पत्र।

महामहिम्

वर्ष 2003 में वीरभद्र सरकार प्रदेश वासियों से लम्बे चौड़े वायदे कर सत्तासीन हुई थी, परन्तु सत्ता में आने पर जनता से किए सभी वायदे भूल गई। वीरभद्र सरकार के गत् 4 वर्ष बढ़ते भ्रष्टाचार, असहनीय मंहगाई व बेलगाम होती बेरोजगारी के साबित हुए हैं, जिसके कारण प्रदेश का हर वर्ग आक्रोशित व निराश है।

हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के जनविरोधी निर्णयों एवं भ्रष्टाचार के काले कारनामों को तथ्यों सहित उजागर करने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसने सरकार के विरूद्ध एक गम्भीर आरोप पत्र तैयार किया है, जो महामहिम् को प्रेषित है।

भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट एवं निक्कमी वीरभद्र सरकार को तुरन्त बर्खास्त किया जाए ताकि इस गरीब विरोधी सरकार से प्रदेश की जनता को मुक्ति मिल सके। सभी आरोपों की जॉच सी0बी0आई0 से करवाई जाए जिससे इस सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया जा सके।

(प्रेम कुमार धूमल)
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता
प्रतिपक्ष हि0प्र0

(जय राम ठाकुर)
प्रदेश अध्यक्ष
भाजपा हि0प्र0

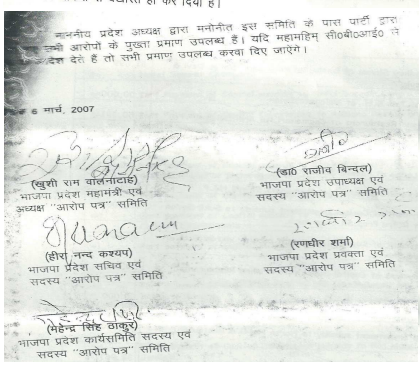

- **कर्मचारी उत्पीड़न**

कांग्रेस सरकार ने उनकी गलत नीतियों पर आवाज़ उठाने वाले और कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारी नेताओं को निलंबित कर दिया और बिजली बोर्ड तथा पर्यटन निगम के कर्मचारी नेताओं को तो बर्खास्त ही कर दिया है। सर्वश्री देव राज शर्मा, होशियार सिंह ठाकुर व सत्यप्रकाश ठाकुर, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष व महामंत्री हि0 प्र0 विद्युत परिषद तकनीकि कर्मचारी संघ को विगत 3 वर्षों से बर्खास्त ही कर दिया गया है।

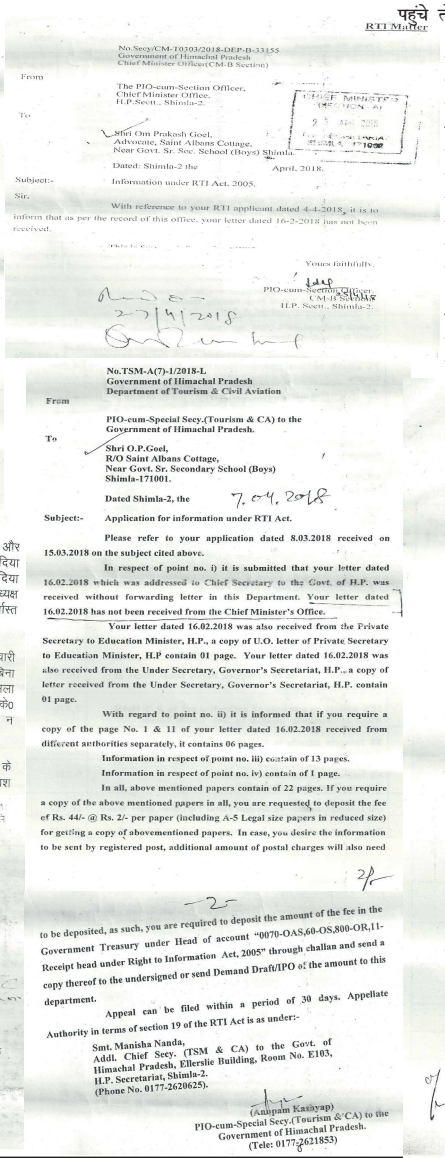

हाल ही में कर्मचारी दुर्घटना बीमा का घोटाला उठाने वाले कर्मचारी परिसंघ के महामंत्री श्री विनोद कुमार को 2 वर्षों में तीन बार स्थानान्तरित और बिना कारण निलंबित कर दिया है। अतना ही नहीं उनकी पत्नी का स्थानान्तरण भी शिमला से किन्नौर के लिए कर दिया है। कर्मचारी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वी0के0 कौल को ढेढ वर्ष में दो बार बदल दिया ताकि वह कर्मचारियों के हितों के मामले न उठा सके।

इसी प्रकार पर्यटन निगम में पर्यटन मंत्री और निगम के निदेशक के भ्रष्टाचार के मामले के विषय में आवाज उठाने वाले कर्मचारी नेता श्री ओम प्रकाश गोयल को नौकरी से बर्खास्त ही कर दिया है।

माननीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मनोनीत इस समिति के पास पार्टी द्वारा सभी आरोपों के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध हैं। यदि महामहिम् सी0बी0आई0 से जांच के आदेश देते हैं तो सभी प्रमाण उपलब्ध करवा दिए जाऐंगे।

6 मार्च, 2007

(खुशी राम बालनाटाह)
भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं
अध्यक्ष "आरोप पत्र" समिति

(डा0 राजीव बिन्दल)
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं
सदस्य "आरोप पत्र" समिति

(हीरा नन्द कश्यप)
भाजपा प्रदेश सचिव एवं
सदस्य "आरोप पत्र" समिति

(रणधीर शर्मा)
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं
सदस्य "आरोप पत्र" समिति

(महेन्द्र सिंह ठाकुर)
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं
सदस्य "आरोप पत्र" समिति

RTI Matter

No.Secy/CM-T0303/2018-DEP-B-33155
Government of Himachal Pradesh
Chief Minister Officer(CM-B Section)

From

The PIO-cum-Section Officer,
Chief Minister Office,
H.P.Sectt., Shimla-2.

To

Shri Om Prakash Goel,
Advocate, Saint Albans Cottage,
Near Govt. Sr. Sec. School (Boys) Shimla.

Dated: Shimla-2 the April, 2018.

CHIEF MINISTER (SECTION - A) 25 APR 2018 SHIMLA 171002

Subject:- Information under RTI Act. 2005.

Sir,

With reference to your RTI applicant dated 4-4-2018, it is to inform that as per the record of this office, your letter dated 16-2-2018 has not been received.

Yours faithfully,

PIO-cum-Section Officer,
CM-B Section
H.P. Sectt., Shimla-2.

27/4/2018

No.TSM-A(7)-1/2018-L
Government of Himachal Pradesh
Department of Tourism & Civil Aviation

From

PIO-cum-Special Secy.(Tourism & CA) to the Government of Himachal Pradesh.

To

Shri O.P.Goel,
R/O Saint Albans Cottage,
Near Govt. Sr. Secondary School (Boys)
Shimla-171001.

Dated Shimla-2, the 7.04.2018

Subject:- Application for information under RTI Act.

Please refer to your application dated 8.03.2018 received on 15.03.2018 on the subject cited above.

In respect of point no. i) it is submitted that your letter dated 16.02.2018 which was addressed to Chief Secretary to the Govt. of H.P. was received without forwarding letter in this Department. Your letter dated 16.02.2018 has not been received from the Chief Minister's Office.

Your letter dated 16.02.2018 was also received from the Private Secretary to Education Minister, H.P., a copy of U.O. letter of Private Secretary to Education Minister, H.P contain 01 page. Your letter dated 16.02.2018 was also received from the Under Secretary, Governor's Secretariat, H.P., a copy of letter received from the Under Secretary, Governor's Secretariat, H.P. contain 01 page.

With regard to point no. ii) it is informed that if you require a copy of the page No. 1 & 11 of your letter dated 16.02.2018 received from different authorities separately, it contains 06 pages.

Information in respect of point no. iii) contain of 13 pages.

Information in respect of point no. iv) contain of 1 page.

In all, above mentioned papers contain of 22 pages. If you require a copy of the above mentioned papers in all, you are requested to deposit the fee of Rs. 44/- @ Rs. 2/- per paper (including A-5 Legal size papers in reduced size) for getting a copy of abovementioned papers. In case, you desire the information to be sent by registered post, additional amount of postal charges will also need

2/-

-2-

to be deposited, as such, you are required to deposit the amount of the fee in the Government Treasury under Head of account "0070-OAS,60-OS,800-OR,11-Receipt head under Right to Information Act, 2005" through challan and send a copy thereof to the undersigned or send Demand Draft/IPO of the amount to this department.

Appeal can be filed within a period of 30 days. Appellate Authority in terms of section 19 of the RTI Act is as under:-

Smt. Manisha Nanda,
Addl. Chief Secy. (TSM & CA) to the Govt. of Himachal Pradesh, Ellerslie Building, Room No. E103,
H.P. Secretariat, Shimla-2.
(Phone No. 0177-2620625).

(Anupam Kashyap)
PIO-cum-Special Secy.(Tourism & CA) to the
Government of Himachal Pradesh.
(Tele: 0177-2621853)

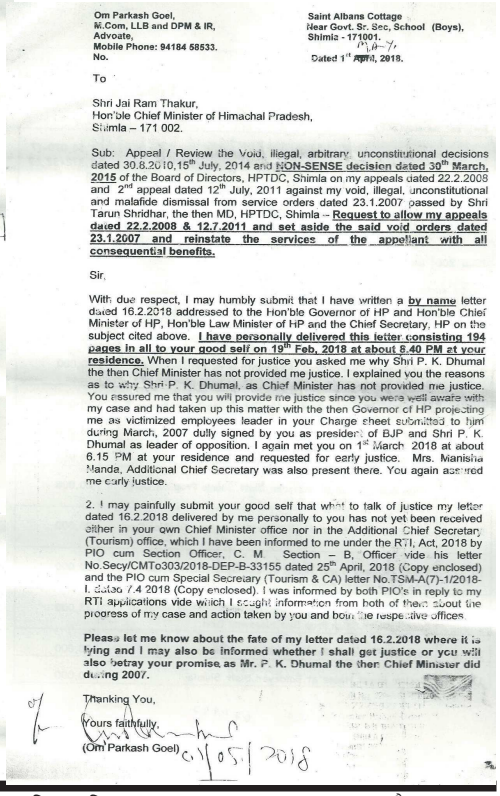

Om Parkash Goel,
M.Com, LLB and DPM & IR,
Advoate,
Mobile Phone: 94184 58533.
No.

Saint Albans Cottage
Near Govt. Sr. Sec, School (Boys),
Shimla - 171001.

Dated 1st April, 2018.

To

Shri Jai Ram Thakur,
Hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh,
Shimla – 171 002.

Sub: Appeal / Review the Void, illegal, arbitrary, unconstitutional decisions dated 30.8.2010, 15th July, 2014 and **NON-SENSE decision dated 30th March, 2015** of the Board of Directors, HPTDC, Shimla on my appeals dated 22.2.2008 and 2nd appeal dated 12th July, 2011 against my void, illegal, unconstitutional and malafide dismissal from service orders dated 23.1.2007 passed by Shri Tarun Shridhar, the then MD, HPTDC, Shimla – **Request to allow my appeals dated 22.2.2008 & 12.7.2011 and set aside the said void orders dated 23.1.2007 and reinstate the services of the appellant with all consequential benefits.**

Sir,

With due respect, I may humbly submit that I have written a **by name** letter dated 16.2.2018 addressed to the Hon'ble Governor of HP and Hon'ble Chief Minister of HP, Hon'ble Law Minister of HP and the Chief Secretary, HP on the subject cited above. **I have personally delivered this letter consisting 194 pages in all to your good self on 19th Feb, 2018 at about 8.40 PM at your residence.** When I requested for justice you asked me why Shri P. K. Dhumal the then Chief Minister has not provided me justice. I explained you the reasons as to why Shri P. K. Dhumal, as Chief Minister has not provided me justice. You assured me that you will provide me justice since you were well aware with my case and had taken up this matter with the then Governor of HP projecting me as victimized employees leader in your Charge sheet submitted to him during March, 2007 dully signed by you as president of BJP and Shri P. K. Dhumal as leader of opposition. I again met you on 1st March 2018 at about 6.15 PM at your residence and requested for early justice. Mrs. Manisha Nanda, Additional Chief Secretary was also present there. You again assured me early justice.

2. I may painfully submit your good self that what to talk of justice my letter dated 16.2.2018 delivered by me personally to you has not yet been received either in your own Chief Minister office nor in the Additional Chief Secretary (Tourism) office, which I have been informed to me under the RTI, Act, 2018 by PIO cum Section Officer, C. M. Section – B, Officer vide his letter No.Secy/CMTo303/2018-DEP-B-33155 dated 25th April, 2018 (Copy enclosed) and the PIO cum Special Secretary (Tourism & CA) letter No.TSM-A(7)-1/2018-L dated 7.4 2018 (Copy enclosed). I was informed by both PIO's in reply to my RTI applications vide which I sought information from both of them about the progress of my case and action taken by you and both the respective offices.

Please let me know about the fate of my letter dated 16.2.2018 where it is lying and I may also be informed whether I shall get justice or you will also betray your promise as Mr. P. K. Dhumal the then Chief Minister did during 2007.

Thanking You,

Yours faithfully,

(Om Parkash Goel) 01/05/2018

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177–2805015, 94180–15015 फैक्सः 2805015

सुक्खु-वीरभद्र द्वन्द में फिर लगी कांग्रेस दाव पर

शिमला/शैल। पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान ने रजनी पाटिल को प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद वीरभद्र सिंह ने फिर से प्रदेश अध्यक्ष सुक्खु को हटवाने की मुहिम छेड़ दी है। इस मुहिम की शुरूआत उन्होने रजनी पाटिल के लिये प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित की गयी पहली ही बैठक मे गैर हाजिर रह कर की। इसके बाद अब प्रदेशभर में अपने समर्थकों की बैठकें करके सुक्खु के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। इन बैठकों के पहले चरण में हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला और बिलासपुर में यह बैठकें की गयी है। इन बैठकों में पार्टी के भीतर बैठे वीरभद्र के वैचारिक विरोधियों को आमन्त्रित तक नहीं किया गया। एक प्रकार से वीरभद्र प्रदेश में समानान्तर कांग्रेस खड़ी करने की लाईन पर चल पड़े हैं। क्योंकि जिस तरह से वीरभद्र ने अपने समर्थकों की बैठकें करके हाईकमान को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हिमाचल में वीरभद्र ही कांग्रेस है। यदि इस दबाव के बाद भी हाईकमान सुक्खु को नहीं हटाती है तब वीरभद्र के पास पार्टी को दो फाड़ करने के अलावा कोई विकल्प शेष नही रह जाता है क्योंकि इस बार वह बहुत दूर निकल आये हैं। वीरभद्र की दबाव की राजनीति और रणनीति के आगे हाईकमान इस बार कितना झुकता है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इसी दवाब की रणनीति के सहारे 1983 में वीरभद्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री बने थे। इसके बाद 1993 में जब सुखराम को हाईकमान का आर्शीवाद मिलने की बात तब वीरभद्र ने विधानसभा का घेराव करवाकर कुर्सी पर कब्जा किया।

इस तरह प्रदेश की राजनीति और वीरभद्र की रणनीति की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि वीरभद्र ने जो हासिल किया है वह दवाब की राजनीति का ही परिणाम रहा है। वीरभद्र 1983 से लेकर अबतक करीब 22 वर्ष प्रदेश के मुख्यमन्त्री रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश जिस स्थिति से गुज़र रहा है उसके लिये वीरभद्र बहुत हद तक जिम्मेदार रहे हैं क्योंकि जब वीरभद्र ने अप्रैल 1983 में प्रदेश संभाला था उस समय प्रदेश के पास 80 करोड़ सरप्लस था यह जानकारी 1998 में जब धूमल ने प्रदेश की वित्तिय स्थिति पर श्वेत पत्र रखा था उसमें दर्ज है। आज प्रदेश का कर्ज पचास हज़ार करोड़ से ऊपर जा चुका है लेकिन यदि यह सवाल पूछा जाये कि इस कर्ज का निवेश कहां हुआ है तो शायद प्रशासन के पास कुछ बड़ा दिखाने लायक नही है। 1990 में जब शान्ता कुमार जेपी उद्योग को प्रदेश में लाये थे तब वीरभद्र ने पूरे प्रदेश में यह आन्दोलन खड़ा कर दिया था कि प्रदेश को नीजि क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। 1993 में सत्ता में आते ही शान्ता काल के बेनामी सौदों पर एसएस सिद्धु की अध्यक्षता में जांच बिठा दी थी परन्तु उसकी रिपोर्ट पर कोई कारवाई नही की थी। 1983 में जिस फारैस्ट माफिया के खिलाफ जिहाद छेड़कर सत्ता हासिल की थी आज उसका आलम यह है कि प्रदेश में वनभूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिये प्रदेश उच्च न्यायालय को कड़े आदेश जारी करन पड़े हैं। इन अवैध कब्जों में भी रोहडू का स्थान प्रदेश में पहले स्थान पर आता है। 1993 से 1998 के बीच सरकारी विभागों और निगमों में हजारों लोगों को चिट्टों पर भर्ती करने का कीर्तिमान भी वीरभद्र सिंह के ही नाम है। यदि अभय शुक्ला और हर्ष गुप्ता कमेटीयों की रिपोर्ट पर धूमल ने कारवाई की होती तो आज प्रदेश की राजनीति का स्वरूप ही कुछ और होता। वीरभद्र के शासन में ही प्रदेश के सहकारी बैंकों का एनपीए ही 900 करोड़ से ऊपर हो

गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आज प्रदेश के रोज़गार कार्यालयों में करीब एक लाख बीएड और एमएड बेरोज़गारों के तौर पर पंजीकृत हैं और दूसरी सरकारी और प्राईवेट स्कूलों में करीब नौ हज़ार ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जिनके पास जेबीटी और बी एड की कोई डीग्री ही नहीं है। प्रदेश की इस स्थिति के लिये सबसे अधिक जिम्मेदार वीरभद्र ही रहे हैं।

व्यक्तिगत तौर पर भी आय से अधिक संपति मामले में जिस तरह से अभी तक वीरभद्र घिरे हुए हैं वह सबके सामने है। ईडी ने जिस तरह से वीरभद्र के साथ सहअभियुक्त बने आनन्द चौहान और वक्का मुल्ला चन्द्र शेखर को गिरफ्तार कर लिया तथा मुख्य अभियुक्त वीरभद्र को छोड़ दिया। इसको लेकर जो चर्चाएं लोगों में चल रही हैं उस पर मोदी सरकार से लेकर वीरभद्र तक किसी के पास भी कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं है। क्योंकि कल तक इस मामले को लेकर जो आरोप पूरी भाजपा लगाती रही है वह आज इस पर जुबान खोलने की स्थिति में नही है लेकिन वीरभद्र भी इस स्थिति में नही है कि वह कह सकें कि मोदी की ऐजैन्सीयों ने उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया था और आनन्द चौहान की गिरफ्तारी एकदम गलत थी। इस परिदृश्य में जब वीरभद्र की सुक्खु हटाओ मुहिम का आकलन किया जाये तो यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यह सब करने में उनकी नीयत क्या है। क्योंकि जब किसी पार्टी की सरकार बन जाती है तब संगठन के जिम्मे उस सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार रहता है। सरकार संगठन पर हावी रहती है संगठन सरकार के आगे एक तरह से बौना पड़ जाता है कम से कम कांग्रेस में तो यही प्रथा रहती आयी है। वीरभद्र सरकार का पिछला कार्यकाल उपलब्धियों के नाम पर बिल्कुल नगण्य रहा है। इस काल में कोई बड़ी परियोजना बड़े निवेश के साथ प्रदेश में नही आ पायी है। आवश्यकता से अधिक ऐसे संस्थान खोल दिये गये जिनको चला पाना किसी के लिये भी संभव नही हो पायेगा। वित्त विभाग वीरभद्र के ईशारे पर नाचता रहा और केवल कर्ज जुटाने की ही जुगाड़ में लगा रहा। भारत सरकार के मार्च 2016 के पत्र की अनदेखी करके कर्ज उठाया जाता रहा। इसलिये यह कहना गलत होगा कि संगठन ने सरकार का साथ नही दिया। बल्कि जब वीरभद्र के लोगों ने वीरभद्र ब्रिगेड बनाकर समानान्तर संगठन खड़ा करने का प्रयास किया था उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि आने वाला समय प्रदेश में कांग्रेस के लिये नुकसानदेह होने जा रहा है और वैसा हुआ भी। क्योंकि वीरभद्र पूरी तरह से कुछ स्वार्थी लोगों से घिर गये थे। आज जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पुनः सशक्त होने के प्रयास कर रही है जिसका संदेश कर्नाटक और उसके बाद हुए उपचुनावों के परिणामों से सामने आ चुका है। ऐसे में वीरभद्र का अपने ही संगठन में कुछ लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलना अप्रत्यक्षतः कांग्रेस को कमज़ोर करके भाजपा को ही लाभ पंहुचाने का प्रयास माना जा रहा है। क्योंकि सुक्खु का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा हो चुका है उनका हटना तय है। वीरभद्र इसे जानते हैं फिर भी वीरभद्र का सुक्खु विरोध सुक्खु को हटाने से ज्यादा अपनी पंसद का अध्यक्ष बनाने का प्रयास ही माना जा रहा है।

शिमला में पहली ही पत्रकार वार्ता में जयराम ने साथ नहीं रखा कोई भी मंत्री

शिमला/शैल। जिस जयराम को वीरभद्र राजनीति में बच्चा करार देते आ रहे हैं उसने पांच माह में ही एशियन विकास बैंक से 4378 करोड़ की योजनाएं पर्यटन, पेयलन और बागवानी क्षेत्र मे स्वीकार कर वीरभद्र और अपने विरोधीयों को बड़ा करारा जबाव दिया है। यही नहीं बल्कि 4751 करोड़ की एक ओर योजना भी स्वीकृति के कगार पर पंहुच चुकी है। जबकि वीरभद्र के शासनकाल में केवल 2011 में ही एक 600 करोड़ की एक योजना पर ही काम हो पाया है। यह जानकारी मुख्यमन्त्री जयराम ने शिमला में अपना पदभार संभालने के बाद आयोजित हुई पहली पत्रकार वार्ता में रखी।

पर्यटन के क्षेत्र में 1892 करोड़ की योजना स्वीकार हुई है और इसका प्रारूप प्रधानमन्त्री को 26 फरवरी 2018 को भेजा गया था। इस योजना को लेकर पत्रकार वार्ता में जो पत्र जारी किया गया है उसमें यह दावा किया गया है कि इस योजना का प्रारूप तैयार करने से पहले प्रदेश के 324 स्थलों का सर्वेक्षण किया औ 90,000 पर्यटकों से पर्यटन के विकास के लिये राय मांगी है। स्वभाविक है कि इतनी बड़ी योजना तैयार करने के लिये इस स्तर का ग्राऊड वर्क किया जाना आवश्यक है लेकिन क्या पर्यटन विभाग ने दो माह में ही 324 स्थलों का सर्वेक्षण भी कर लिया और 90,000 पर्यटकों से राय भी ले ली? इतना आधारभूत काम करने के लिये तो कम से कम एक वर्ष का समय चाहिये जबकि अभी सरकार को सत्ता में आये छः माह भी पूरे नही हुए हैं। लेकिन मुख्यमन्त्री ने पत्रकार वार्ता में दावा किया है कि यह योजना एकदम मौलिक है और पूर्व सरकार के समय इसका स्वप्न तक नही लिया गया था। स्वभाविक है कि दावा विभाग द्वारा दी गयी फीडबैक पर आधारित रहा होगा जिसकी व्यवहारिक प्रसांगिकता पर किसी ने ध्यान नही दिया है।

इसी तरह बागवानी के क्षेत्र में भी 1688 करोड़ की योजना स्वीकृत होने का दावा किया गया है। इस योजना से प्रदेश के निचले क्षेत्रों के किसान और बागवान लाभान्वित होगें। इस योजना से पहले भी एशियन विकास बैंक से पोषित एक योजना बागवानी के क्षेत्र में चल रही है जिसको लेकर

वर्तमान बागवानी मंत्री मेहन्द्र सिंह ठाकुर और पूर्व मन्त्री विद्या स्टोक्स में काफी लंबी जुबानी जंग भी रही है क्योंकि विद्या स्टोक्स यह दावा करती रही है कि पूर्व योजना में भी प्रदेश के निचले क्षेत्र बराबर शामिल रहे हैं लेकिन महेन्द्र सिंह स्टोक्स के इस दावे को सिरे से खारिज करते रहे हैं। इस योजना के आकार लेते समय यह सवाल अवश्य उठेगा कि एक ही ऐजैन्सी एक ही योजना पर दो बार सही में ही धन दे रही है या इसमें भी विभाग द्वारा मन्त्री के सामने तथ्य रखने में कोई चूक हुई है। इसपर स्थिति तब स्पष्ट होगी जब विकास बैंक की टीम डीपीआर का आकलन करने आयेगी।

सिंचाई एवम् जनस्वास्थ्य विभाग के तहत 2001 से पहले की निर्मित 1421 पेयजल योजनाओं के संवर्द्धन के लिये 798.19 की करोड़ की एक योजना स्वीकृत हुई है। इस योजना के लिये 80% धन एशियन विकास बैंक उपलब्ध करवायेगा और 20% (159.54 करोड़) राज्य सरकार को अपने साधनों से जुटाना होगा यह जानकारी इस आश्य के जारी हुए प्रेस नोट में दी गयी है। जबकि मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव जो पहले वित्त सचिव भी थे ने यह दावा किया है कि इन योजनाओं के लिये राज्य सरकार को केवल 10% के ही अपने हिस्से के रूप में देना होगा। 10% के हिस्से की शर्त एशियन विकास बैंक की सभी योजना पर लागू होगी या केवल पर्यटन और बागवानी पर ही होगी यह स्पष्ट नही हो पाया है।

एशियन विकास बैंक की इन योजनाओं को जमीनी आकार लेने में समय लगेगा। क्योंकि यह स्वीकृतियां अभी सिन्द्धात रूप में ही मिली है। इसके बाद इनकी डीपीआर बनेगी और उसका निरीक्षण विकास बैंक की टीम करेगी उसके बाद ही एम ओ यू साईन होंगे। इतना योजनाओं की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलना भी अपने में एक उपलब्धि है। लेकिन इसको लेकर समय समय पर खबरें छपती भी रही हैं ऐसे में क्या इन योजनाओं को लेकर इस स्टेज पर ही मुख्यमन्त्री द्वारा पत्रकार वार्ता किया जाना आवश्यक था या नही इसको लेकर भी चर्चाएं चल पड़ी है। क्योंकि इन योजनाओं को इस अंजाम तक पंहुचाने में संबधित मन्त्रीयों का भी योगदान रहा है ऐसे में इस मौके पर संवद्ध मन्त्री का भी साथ होना बनता था। फिर राजधानी में मुख्यमन्त्री बनने के बाद यह जयराम की पहली प्रैस वार्ता थी। विपक्ष इस समय सरकार और मुख्यमन्त्री पर यह आरोप लगा रहा है कि सारे मन्त्री और विधायक उन्हे सहयोग नही दे रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता में किसी भी मन्त्री का उनके साथ शामिल न रहना केवल यही संकेत देता है कि यह वार्ता अधिकारियों की सलाह पर बुलायी गयी थी क्योंकि इसकी जानकारी मीडिया को केवल तीन घन्टे पहले ही दी गयी थी। फिर इस वार्ता में पर्यटन को लेकर मुख्यमन्त्री से यह दावा करवा दिया गया कि यह विचार यह विज़न केवल अभी की उपज है जबकि प्रैस नोट में दर्ज आंकड़े इसको सत्यापित नही करते है। स्वभाविक है कि सरकार द्वारा स्वयं अपने ही प्रैस नोट में दिये गये आंकड़ों के आधार पर मुख्यमन्त्री के दावे पर विपक्ष सवाल खड़े करेगा जिनका कोई तर्क संगत जवाब नही होगा।

मुख्यमन्त्री ने पत्रकार वार्ता में जिस तर्ज पर वीरभद्र और मुकेश अग्निहोत्री पर हमला बोला है उसकी धार के पहली ही प्रैस वार्ता में मन्त्रीयों और पार्टी के पदाधिकारियों का साथ न होना स्वयं ही कुन्द कर जाता है। इस वार्ता से स्वतः ही यह संदेश गया है कि मुख्यमन्त्री अपने मन्त्रीयों से अधिक अधिकारियों पर ज्यादा निर्भर कर रहे हैं और यह भूल रहे हैं कि कल तक यही अधिकारी वीरभद्र के हर फैसले का ऑख बन्द करके अनुमोदन कर रहे थे। इन्ही के गलत फैसलों का परिणाम है कि आज स्कूलों में अध्यापकों के लिये बच्चों को हड़ताल करनी पड़ रही है और दवाब में एक प्रधानाचार्य की हार्टअटैक से मौत तक हो गयी है।